सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

भोपाल

सोमवार, 07 अक्टूबर, 2024

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-40 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

पहली बात

लड्डू विवाद : सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर सियासी खामोशी

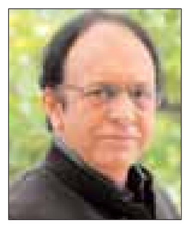

उमेश त्रिवेदी

संपादक

9893032101

तिरूमला तिरूपति देवस्थानम् के लड्डू-विवाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की टिप्पणियों के राजनैतिक रूप से दो ऑपरेटिव-पार्ट हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने सियासी पार्टियों और नेताओं से आव्हान किया है कि वो ईश्वर को राजनीति से दूर रखें। दूसरा, बैंच ने आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को उनके अधकचरे बयान पर नसीहत देकर संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को आगाह किया है कि सियासी नफे-नुकसान के खेल में आम जनता की आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं करें। वो शासन-प्रशासन की अधकचरी सूचनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करके लोगों के विश्वास और आस्थाओं को उद्वेलित नहीं करें।

सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दलों को झिड़कते हुए स्पष्ट कहा है कि 'ईश्वर को राजनीति से दूर रखें।' सुप्रीम कोर्ट की नसीहत देश के मौजूद राजनीतिक चरित्र पर सीधा प्रहार है। बहरहाल, भारत में धर्म प्रधान राजनीति के इस दौर में 'ईश्वर को राजनीति से दूर रखने' का यह न्यायिक आव्हान भावनात्मक रूप से लोकतंत्र की किताब में एक बहस के रूप में भले ही दर्ज हो जाए, लेकिन सत्ता के सिंहासन के नजदीक यह कदाचित ही कोई स्पंदन पैदा कर सकेगा। सत्ता की अवधारणाएं ईश्वर जैसी निराकार नहीं होती हैं। वह देश, काल और समाज की बेशरम जरूरतों एवं बेमुरव्वत हकीकतों से संचालित होती हैं। धर्म प्रधान राजनीति वर्तमान कालखंड का कठोर सच है। यह भी सच है कि धर्म की धुरी ईश्वर ही है। ईश्वर और धर्म के यह अंतर्सम्बंध स्वतः ही ईश्वर को राजनीतिक के घेरे में ढकेल देता है।

इस परिप्रेक्ष्य में सियासी दल भले ही कुछ कहें, लेकिन धर्म विमुख होकर वो कतई अपनी राजनीति नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह कथन राजनीतिक दलों के सियासी चरित्र और सत्ता-संस्थानों की लोकतांत्रिक धारणाओं को चुनौती देता-सा महसूस होता है। दिलचस्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कथन पर बगलें झांकती किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अभी इसे मंजूर नहीं किया है। यह प्रश्न और उसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है कि देश की सुप्रीम कोर्ट की नसीहतें कारगर साबित हो पाएंगी ? यह भी नहीं लगता कि देश की सियायत और सियासी दल ने इसे गंभीरता से सुनकर समझने की कोशिश भी की है ?

आंध्र प्रदेश के सेशाचालाम पर्वत पर स्थित तिरूमला तिरूपति देवस्थानम् में लड्डूओं के प्रसाद में चर्बी की मिलावट की खबर ने देश के जनमानस को हिला सा दिया है। तिरूमला मंदिर की मान्यता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर को हर साल करीब एक टन सोना दान में मिलता है। ये लड्डू मंदिर के गुप्त रसोई घर में तैयार किए जाते हैं। यह रसोई घर पोटू कहलाता है। यहां रोजाना हजारों लड्डू तैयार किये जाते हैं, जिन्हे रोज आने वाले दर्शानार्थियों को बांटा जाता है।

भारत में लोकतंत्र सत्ता हासिल करने के एक ऐसी अनियंत्रित प्रतियोगिता में तब्दील हो गया है, जिसमें लोकतंत्र की परम्परागत मर्यादाओं और संवैधानिक नियमावली के लिए कोई जगह नहीं होती है। लोकतंत्र सत्ता का वह अखाड़ा बन चुका है, जहां पक्ष-विपक्ष के नेता कमर के नीचे हमला करने में भी नहीं चूकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का लोकतंत्र अब दुश्मनों की राजनीति का मैदान बन चुका है, जहां परस्पर दुश्मनी के चलते एक-दूसरे को नेस्तनाबूद करने के खेल ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली है। पांच साल बाद आंध्र प्रदेश की सत्ता में लौटे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू व्दारा तिरूमला तिरूपति देवस्थानम् में लड्डू विवाद का खुलासा सियासी दुश्मनी के खेल की इसी श्रेणी में आता है।

आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को राजनीतिक रूप से ठिकाने लगाने के लिए जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने तिरूपति मंदिर के लड्डुओं में चर्बी की मिलावट की खबर का खुलासा किया, उसे लोग सियासी दुश्मनी के मारक खेल का हिस्सा ही मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र बाबू नायडू के इस खुलासे को असामयिक, गैर-जरूरी, अधकचरा और तथ्यों से खिलवाड़ माना है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के कृत्य पर सख्त टिप्पणी की है। देश के वरिष्ठ नेताओं की करतूतों पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रियाओं में यह टिप्पणी अपवाद मानी जाएगी। चंद्रबाबू नायडू को देश के सर्वश्रेष्ठ और दूरद्रष्टा नेताओं में शुमार किया जाता है। लेकिन तिरूपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी की मिलावट की बात ने देश की आस्थाओं पर आघात किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू से कहा है कि ''आप संवैधानिक पद पर हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। अगर आपने पहले जांच के आदेश दे दिए थे,तो मीडिया मे जाने की क्या जरूरत थी? प्रयोगशाला की रिपोर्ट जुलाई मे आ गई थी। आपका बयान सितंबर में आया। रिपोर्ट में सब कुछ साफ नही है।'' उल्लेखनीय है कि चंद्रबाबू नायडू ने 19 सितम्बर को दावा किया था कि- 'पिछली सरकार के दौरान तिरूमला मंदिर में लड्डू को बनाने में शुद्ध घी के बजाय जानवरों की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल होता था'।

सवाल यह है कि राजनीतिक बयानों की लक्ष्मण रेखा क्या होना चाहिए? संविधान लोगों को अपनी बात रखने की इजाजत देता है, लेकिन राजनीतिक बयानों की भी एक मर्यादा रेखा होना चाहिए कि वह किस तरीके से लोगों के जनमानस को उद्वेलित करता है। संविधान के जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। नायडू के गैर-जिम्मेदार और अधकचरे बयान ने समूचे हिंदू-समाज की आस्थाओं पर प्रहार किया है। सिर्फ तिरूपति मंदिर में हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। नायडू ने उन्हें पश्चाताप और पाप की मनोदशा में ढकेलने का काम किया है।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट की दोनों प्रतिक्रियाओं पर टीवी एंकरों और राजनीति कवर करने वाले धुरंधर पत्रकारों के लिए भले ही कुछ मसाला हो, लेकिन दोनों मामलों में सियासी पार्टी और नेताओं की खामोशी कहती है कि बात दूर तलक कतई नहीं जाएगी। समय के साथ सब कुछ दफ्न हो जाएगा।

भोपाल में 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त

बंद पड़ी फैक्ट्री में गुजरात एटीएस और एनसीबी की रेड, दो आरोपी गिरफ्तार

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने एटीएस गुजरात के साथ मिलकर शनिवार को एक फैक्ट्री में रेड की, जहां ड्रग्स बनाई जा रही थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जिन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए गुजरात एटीएस ने रविवार को भोपाल न्यायालय में पेश किया। पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को रविवार को ही गुजरात ले जा रही है।

ड्रग्स को भोपाल के नजदीक एक फैक्ट्री से बरामद किया गया है। यह फैक्ट्री बगरोदा गांव के इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो कटारा हिल्स थाना इलाके में स्थित है। खास बात यह है कि गुजरात एटीएस और एनसीबी की इस कार्रवाई की मध्यप्रदेश के खुफिया विभाग को खबर तक नहीं लगी।

फैक्ट्री में हो रहा था मादक पदार्थ मेफेड्रोन (एमडी) बनाने का काम

डीएसपी, एटीएस गुजरात एस.एल. चौधरी ने बताया- यह सूचना मिली थी कि भोपाल का अमित चतुर्वेदी और नासिक- महाराष्ट्र का सान्याल बाने भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री की आड़ में मादक पदार्थ मेफेड्रोन (एमडी) के अवैध निर्माण और बिक्री में शामिल हैं। जिसके बाद गुजरात एटीएस के सीनियर अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

मुख्य आरोपी पांच साल जेल में रह चुका है

आरोपियों में सान्याल प्रकाश बाने (उम्र 40 वर्ष) महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है और अमित चतुर्वेदी (उम्र 57 वर्ष) भोपाल का रहने वाला है। सान्याल प्रकाश बाने को इससे पहले साल 2017 में महाराष्ट्र के अंबोली पुलिस स्टेशन इलाके में एक किलो एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उसे पांच साल की जेल भी हुई थी।

5 अक्टूबर को फैक्ट्री पर की गई थी रेड

छापा मार कार्रवाई 5 अक्टूबर को की गई थी। इस दौरान पता चला कि यहां मादक दवा मेफेड्रोन (एमडी) बनाने का काम चल रहा था। इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला करीब 5 हजार किलोग्राम का कच्चा माल और उपकरण भी मिले। इनमें ग्राइंडर, मोटर, ग्लास फ्लास्क, हीटर और अन्य उपकरण शामिल हैं। इन सभी सामग्रियों को आगे की जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। फैक्ट्री में तलाशी के दौरान कुल 907.09 किलोग्राम मेफेड्रोन (ठोस और तरल दोनों रूप में) मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 1814.18 करोड़ रुपए है।

रोजाना तैयार कर रहे थे 25 किलो ड्रग्स

गुजरात में पकड़ाए कुछ ड्रग्स डीलर्स से गुजरात एटीएस को इस फैक्ट्री की जानकारी मिली थी। इसके बाद से ही गुजरात एटीएस डेढ़ महीने से फैक्ट्री पर नजर रख रखी थी। जानकारी पक्की होने पर एटीएस ने दिल्ली एनसीबी से संपर्क किया। इसके बाद संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में आरोपी पिछले छह महीने से रोजाना 25 किलो ड्रग्स तैयार कर रहे थे। आरोपियों ने फैक्ट्री 6 महीने पहले किराए पर ली थी। ये फैक्ट्री भोपाल के किसी ए.के. सिंह की बताई जा रही है।

भारत विश्व गुरु के रूप में शिक्षक परंपरा को स्थापित करना चाहता है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज के मार्ग पर चलने से ही शिक्षा व्यवस्था होगी बेहतर

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गुरुकुल परंपरा हमारे देश की शिक्षा का आधार रही है। शिक्षक हमेशा पूज्य थे और पूज्य रहेंगे। भारत विश्व गुरु के रूप में उस शिक्षक परंपरा को स्थापित करना चाहता है, जो गुरुकुल परंपरा चाणक्य से चंद्रगुप्त तक और चंद्रगुप्त से विक्रमादित्य तक हर जगह, हर समय, हर काल में कायम रही है। मुख्यमंत्री रविवार को रवीन्द्र भवन सभागार में शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह का आयोजन मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री सुरेश सोनी, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह, राज्यसभा सदस्य स्वामी उमेश नाथ जी महाराज कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान - 2024 से डॉ. रामचंद्रन आर., प्रोफेसर के.के. अग्रवाल और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया को सम्मानित किया।

गुरु और गुरुकुल परंपरा में गुरु का विशेष महत्व - मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज के उद्देश्य से आयोजित शिक्षक समारोह के आयोजन में शैक्षिक फाउंडेशन और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत की गुरु और गुरुकुल परंपरा में गुरु का बड़ा महत्व है। इतिहास में जब भी कोई प्रश्न खड़े हुए तो गुरु की भूमिका सामने आई। यदि भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को गुरु वशिष्ठ वनवास के लिए नहीं ले जाते तो रामायण में राम का चरित्र अधूरा रहता। भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा में गुरु सांदीपनि का उज्ज्वल चरित्र शिष्यों के लिए अनुकरणीय और चुनौतियों में प्रेरणा का स्त्रोत रहा है।

शिक्षा न तो सत्ता की दासी है और न ही कानून की किन्करी :सुरेश सोनी

अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री सुरेश सोनी ने कहा कि वास्तव में विकास तभी हो सकता जब हमारे आसपास के परिवेश और जीवन मूल्यों का विकास हो। उन्होंने 1928 में गुजरात विद्यापीठ में दिए गए काका कालेलकर के संबोधन को उद्धत करते हुए कहा कि शिक्षा ने अपने स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा कि शिक्षा न तो सत्ता की दासी है और न ही कानून की किन्करी है, न ही यह विज्ञान की सखी है औप न ही कला की प्रतिहारी यह अर्थशास्त्र की बांदी, शिक्षा तो धर्म का पुनर्रागमन है, यह मानव के हृदय, मन और इन्द्रियों की स्वामिनी है। मानव शास्त्र और समाज शास्त्र, इनके दो चरण हैं, तर्क और निरीक्षण शिक्षा की दो आँखें हैं, विज्ञान मस्तिष्क, इतिहास कान और धर्म शिक्षा के हृदय है।

सुप्रभात

दिल के ज़ख्मों का भी जवाब नहीं
कितने गहरे हैं ये हिसाब नहीं
ज़िंदगी ने दिया बहुत लेकिन
आप जैसा कोई खिताब नहीं
क्यों नशा आपका चढ़ा मुझको
आप तो आप हैं शराब नहीं
राह मंज़िल की है शिकस्ता कुछ
ये सफ़र ज़िंदगी का ख्वाब नहीं
हर कोई पढ़ के जान जाए इसे
दिल की हसरत कोई क़िताब नहीं
सब मुकद्दर का है ये खेल सुनो
मेरा अपना ये इज़्तिराब नहीं
कहकशां तक है नूर तेरा सनम
मरहले तक ही आब-ओ-ताब नहीं।

\- कुसुम शर्मा अंतरा

नाम भले ही बाद में आया लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र है

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। आरएसएस प्रमुख ने बताया कि समाज को कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जहां संगठन, सद्भावना और श्रद्धा हो। लोगों में अनुशासन हो। साथ ही देश के प्रति अपने दायित्व को समझे और उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो। आरएसएस चीफ मोहन भागवत राजस्थान में स्वयंसेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय विवादों को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू हर किसी को अपना मानते हैं और सभी को गले लगाते हैं। इस दौरान आरएसएस प्रमुख ने 3 हजार 827 स्वयंसेवकों को संबोधित किया।

- **भागवत बोले-हिंदुओं को एकजुट रहना होगा, मतभेद-विवाद को भुलाना होगा**

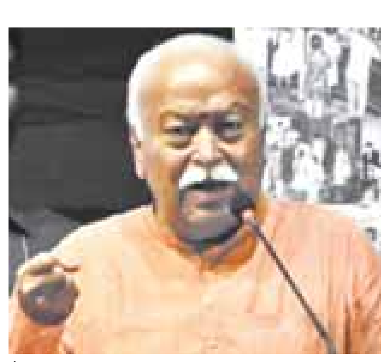

वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस पर चेन्नई में एयर शो

पहले वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हार्वर्ड एयरक्राफ्ट ने कलाबाजियां दिखाईं, सारंग, तेजस ने बनाए कई फॉर्मेशन

चेन्नई (एजेंसी)। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपना 92वां स्थापना दिवस मनाने वाली है। इससे पहले 6 अक्टूबर को चेन्नई के मरीना बीच पर एयर शो हुआ। जिसमें राफेल, सूर्यकिरण और सारंग समेत 72 एयरक्राफ्ट्स ने करतब दिखाए। शो का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट प्रथम विश्वयुद्ध में इस्तेमाल हार्वर्ड एम-6जी टैक्सन एयरक्राफ्ट रहा। भारतीय वायुसेना ने 1974 तक हार्वर्ड को इंटरमीडिएट ट्रेनर के रूप में इस्तेमाल किया था। एयर वाइस मार्शल के प्रेमकुमार के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां 15 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। शो में एडवांस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, सारंग, सुखोई 30 एमकेआई, सी17, सी-295, अपाचे, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, डकोटा जैसे हैरिटेज एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए। चेन्नई में 21 साल बाद एयर शो 21 साल के बाद

चेन्नई में कोई फ्लाईपास्ट और एरियल डिस्प्ले शो हुआ। भारतीय वायुसेना ने तीसरी बार स्थापना दिवस पर होने वाला एयर शो दिल्ली से बाहर आयोजित किया। पिछले साल यह शो 8 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम क्षेत्र में हुआ था। 2022 में इसे चंडीगढ़ में रखा गया था। वायुसेना प्रमुख बोले- 2047 तक सभी हथियार भारत में बनाने का लक्ष्य एयरफोर्स डे से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि भारत को सैन्य उपकरण बनाने के मामले में टेक्नोलॉजी और स्पीड के मामले में चीन से आगे निकलने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा था कि वायुसेना का लक्ष्य स्वदेशीकरण कार्यक्रम के तहत 2047 तक अपने सभी हथियारों का प्रोडक्शन भारत में ही करना है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को आपूर्ति में देरी की भरपाई के लिए हर साल 24 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन करना चाहिए।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 36.3°c
न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार, 07 अक्टूबर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

धैर्य की सीमा पार हो चुकी है, अब कोई मुरव्वत नहीं

- **प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड को लेकर भड़का सुप्रीम कोर्ट**

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतिम मौका देते हुए कहा कि वे 19 नवंबर तक इस मामले में आवश्यक कदम उठाएं वरना उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, हमने अपना धैर्य खो दिया है। अब और कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हम आपको अंतिम अवसर दे रहे हैं। अगर आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया, तो आपके सचिव को कोर्ट में हाजिर रहना होगा। वहीं केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि प्राथमिकता वाले परिवारों के तहत प्रति परिवार एक ही राशन कार्ड जारी किया जाता है, जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट

2020 में स्वतः संज्ञान लेते हुए कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिकों की परेशानियों और कष्टों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने 2021 में दिए गए अपने फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन कार्ड और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। 29 जून, 2021 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कल्याणकारी उपाय करने होंगे, जिसमें राशन कार्ड जारी करना और ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण शामिल है। उल्लेखनीय है कि ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जिसे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा उपायों की पहुंच सुनिश्चित करना है। 2021 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्लू) बनाने में देरी को अक्षम्य करार दिया था और 31 जुलाई, 2021 तक इसका संचालन शुरू करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सभी प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया जाए और कोविड संकट के दौरान उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले।

किसी भी चुने हुए सरपंच को हटाना गंभीर मामला

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलटा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत की सरपंच को पद से हटाने के केस को गंभीर मामला बताया है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाने को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर तब, जब यह ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से जुड़ा हो। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए 27 सितंबर को कोर्ट ने कार्यकाल पूरा होने तक सरपंच की बहाली के आदेश दिए।

सुरेश सौरभ की लघुकथा पुरस्कृत

लखीमपुर खीरी। साहित्यकार सुरेश सौरभ देश की प्रतिष्ठित पत्रिका कथादेश की अखिल भारतीय लघुकथा प्रतियोगिता में स्थान पाकर जनपद का नाम रौशन किया है। उनकी लघुकथा पापी ने आठवां स्थान प्राप्त किया। संपादक हरिनारायण ने उन्हें एक हजार सम्मान राशि प्रेषित की। सौरभ की अनेक रचनाएं प्रतिष्ठित पत्रिकाओं अखबारों में छप रहीं हैं। तालाबंदी, नोटबंदी, निर्भया, मन का फेर, घरों को ढोते लोग, एक कवयित्री की प्रेमकथा आदि इनकी पुस्तकें छप चुकी हैं।

संक्षिप्त समाचार

पंचम मां स्कंदमाता

देवी मां का पांचवां रूप स्कंदमाता के नाम से प्रचलित है। भगवान् कार्तिकेय का एक नाम स्कन्द भी है जो ज्ञानशक्ति और कर्मशक्ति के एक साथ सूचक है। स्कन्द इन्हीं दोनों के मिश्रण का परिणाम है।

देश में 2026-27 में रिटायर होंगे एक लाख अग्निवीर

- इनमें से 42 फीसदी को शुरू हुई सरकारी नौकरी की तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। अग्निवीरों के पहले लॉट से 2026-27 में रिटायर होने वाले जवानों में से 42 फीसदी को सरकारी नौकरियों में लिया जाएगा। यह संख्या उन 25 फीसदी अग्निवीरों से अलग हैं, जिन्हें सेना में समायोजित करना है। यानी सेना में

समायोजित होने से बचे हुए 75 फीसदी जवान केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समायोजित होंगे। शुक्रवार को एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने 25 फीसदी से ज्यादा अग्निवीरों को भारतीय वायु सेना में शामिल करने की इच्छा जताई थी। अग्निवीरों के पहले लॉट का कार्यकाल 2026-27 में पूरा होगा। यह संख्या 1 लाख के करीब है। इनमें 25 हजार सेना में नियमित हो जाएंगे।

उत्तरप्रदेश में मायावती को उपचुनाव से पहले बड़ा झटका

- अलीगढ़ में बसपा प्रत्याशी रहीं चारू केन कांग्रेस में शामिल

अलीगढ़ (एजेंसी)। यूपी में होने वाली उपचुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को बड़ा झटका लगा है। अलीगढ़ से बसपा की प्रत्याशी रहीं डॉ चारू केन ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने

चारू केन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। चारू केन 2022 में अलीगढ़ की खैर सीट से बसपा की प्रत्याशी थीं और यहां उपविजेता रहीं थीं। चारू को 66 हजार से ज्यादा वोट मिले थे। चारू के कांग्रेस में शामिल होने से न सिर्फ बसपा का झटका लगा है बल्कि सपा में भी हलचल बढ़ गई है। अभी सपा-कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है।

चेन्नई मेट्रो के लिए एनडीए सरकार ने दी धन की मंजूरी

स्टालिन सरकार पर मेहरबान केंद्र, एनडीए सहयोगियों को भी संदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-2 के अनुमानित लागत का करीब 65 प्रतिशत खर्च वहन करने का फैसला लिया है। पत्र सूचना कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 को केंद्रीय क्षेत्र परियोजना के रूप में मंजूरी दी है। केंद्र सरकार 63,246 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का लगभग 65 प्रतिशत वित्तपोषित करेगी। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दरअसल, अब

तक इस प्रोजेक्ट को राज्य क्षेत्र परियोजना के रूप में लागू किया जा रहा था, जिसमें परियोजना वित्तपोषण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से तमिलनाडु सरकार पर थी, जो अनुमानित परियोजना लागत का लगभग 90 प्रतिशत था।

झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी ने कर दिए 5 बड़े वादे

दो मुफ्त सिलेंडर, महिलाओं के लिए 'गोगो दीदी योजना, युवाओं के लिए भी खास ऐलान

रांची (एजेंसी)। झारखंड और महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है। झारखंड विधान सभा चुनाव को बीजेपी काफी गंभीरता से ले रही है।

इस बीच झारखंड बीजेपी ने चुनाव से पहले 5 बड़ी योजनाओं को लागू करने का वादा किया है। बीजेपी ने अपनी घोषणा में सरकार बनने पर महिलाओं को कैश बेनिफिट, खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर, नौकरियां, बेरोजगारी भत्ता और आवास देने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इस दौरान मौजूद रहे। भाजपा 'गोगो दीदी योजना' शुरू करेगी, जिसके तहत हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की प्रत्येक महिला के बैंक खाते में 2,100 रुपये तक की वित्तीय सहायता ट्रांसफर की जाएगी।

कोलकाता में आर-पार के मूड में हैं जूनियर डॉक्टर्स

डेडलाइन खत्म होते ही आमरण अनशन कर दिया शुरू

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने शनिवार शाम को आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं कीं। चिकित्सक कोलकाता के मध्य में स्थित धर्मतला इलाके में डोरीना क्रॉसिंग पर शुक्रवार को धरना पर बैठे थे। उन्होंने राज्य सरकार को वादे के अनुसार अपनी मांगें पूरी करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था।

एक जूनियर डॉक्टर ने कहा, 'राज्य सरकार समय सीमा के भीतर हमारी मांगें पूरी करने में विफल रही, इसलिए हम

अपनी मांगें पूरी होने तक आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हमने उस मंच पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जहां हमारे साथी अनशन करेंगे। हम अपने वादे के अनुसार ड्यूटी पर जाएंगे लेकिन हम कुछ भी नहीं खाएंगे।' उन्होंने बताया कि अभी 6 जूनियर डॉक्टर्स अनशन कर रहे हैं। इनमें कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्निग्धा हाजरा, तान्या पांजा और अनुष्टुप मुखोपाध्याय, एसएसकेएम के अर्नब मुखोपाध्याय, एन.आर.एस. मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पुलस्थ आचार्य और के.पी.सी मेडिकल कॉलेज की सायंतनी घोष हाजरा शामिल हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि अगर अनशन के दौरान किसी चिकित्सक की तबियत खराब होती है तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा, 'हमें लोगों का समर्थन प्राप्त है और यही कारण है कि हम प्रशासन की किसी भी तरह की बाधा से नहीं डरते। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे।' कनिष्ठ चिकित्सकों के विरोध स्थल पर शाम को बड़ी संख्या में आम लोग और कुछ मशहूर हस्तियां मौजूद थीं। जूनियर डॉक्टर्स ने पूर्ण कामबंदी वापस लेने के बाद अनशन शुरू किया है।

महाराष्ट्र में महायुति से रामदास अठावले खफा

- कहा-17 लोकसभा सीटों की जीत में हिस्सेदारी हमारी, विधानसभा में भी हो हमारा सम्मान

मुंबई/छत्रपति संभाजीनगर (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव में महायुति के लिए 17 सीटें जीतने में

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रमुख भूमिका निभाई है। फिर भी महाराष्ट्र में हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारी मांग है कि महायुति विधानसभा चुनाव में आरपीआई को 8 से 10 सीटें दे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को अपने कोटे से तीन-तीन सीटें देनी चाहिए।

दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल बोले-हिम्मत है तो मोदी नवंबर में दिल्ली चुनाव कराएं

एनडीए शासित सभी राज्यों में मुफ्त बिजली देंगे तो मैं भाजपा के लिए करूंगा प्रचार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और एएपी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव करके दिखाएं। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं तो मान लें कि वे हार गए, डर गए। केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री दिल्ली चुनाव से पहले एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देने की घोषणा करेंगे तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। केजरीवाल बोले- हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में डबल इंजन सरकारें खत्म हो रहीं केजरीवाल ने कहा,

मैंने कल टीवी पर एग्जिट पोल देखा। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में भाजपा की डबल इंजन सरकारें खत्म हो रही हैं। पहला इंजन जून में फेल हुआ था, जब उन्हें 240 सीटें मिलीं। झारखंड और महाराष्ट्र में भी यही होगा। तब दूसरा इंजन भी फेल हो जाएगा। डबल इंजन सरकार का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में आकर ये (भाजपा) कहेंगे कि डबल इंजन सरकार बना लो। आप तब पूछना कि 10 साल हरियाणा में डबल इंजन सरकार रही। उन्होंने ऐसा क्या किया है कि लोग उनके नेताओं को अपने गांवों में नहीं जाने दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, यूपी में पिछले 7 साल से डबल इंजन की सरकार है। लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें आधी हो गईं।

एमबीए ग्रेजुएट ने अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से कमाए 10 करोड़

- 5 राज्यों में फैला रखा था कारोबार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में आठ सदस्यीय एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चला रहा था। यह गिरोह

पिछले छह साल से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में सक्रिय था। गिरोह के कुछ सदस्य अस्पतालों में काम कर रहे थे, जिससे उन्हें संभावित दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने में मदद मिलती थी। पुलिस ने इस रैकेट पर नजर रखी थी, और अंततः जून में इसकी गतिविधियों का भंडाफोड़ किया। जांच के दौरान पुलिस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि रैकेट का मास्टरमाइंड कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक एमबीए स्नातक संदीप आर्य (39) था।

इजरायल का गाजा में मस्जिद और स्कूल पर बड़ा हमला

देर अल-बला (एजेंसी)। गाजा पट्टी की एक मस्जिद और स्कूल पर इजराइली हवाई हमले में रविवार तड़के कम से कम 24 लोगों की मौत हो गयी। 93 लोग घायल हो गए। फलस्तीनी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इजराइल ने ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ युद्ध का

- **24 लोगों की हो गई मौत, लेबनान में भी सैनिक कार्रवाई जारी**

दायर बढ़ाते हुए उत्तरी गाजा और दक्षिणी बेरूत में बमबारी तेज कर दी है। इजराइल सात अक्टूबर को हमास के हमले के करीब एक साल बाद भी उससे लड़ रहा है और उसने लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। मध्य देर अल-बला शहर के मुख्य अस्पताल के समीप एक मस्जिद में शरण लेने वाले विस्थापित लोगों पर हमला किया गया। इजराइल ने सबूत उपलब्ध कराए बिना कहा कि उसने हमास के कमांड एवं नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया है। 'एसोसिएटेड प्रेस' के एक पत्रकार ने अल-अक्सा

शहीद अस्पताल के मुर्दाघर में शवों की गिनती की। अस्पताल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि सभी मृतक पुरुष थे। एक अन्य पुरुष गंभीर रूप से घायल है। इस बीच, सेना ने उत्तरी गाजा के जबालिया में नए सिरे से हवाई और जमीनी आक्रमण शुरू करने की घोषणा की, जहां इजराइल की स्थापना के आसपास 1948 के युद्ध के घनी आबादी वाले शरणार्थी शिविर स्थित हैं। उसने कई तस्वीरें और वीडियो प्रसारित की हैं जिनमें इलाके की ओर जा रहे कई टैंक दिखायी दे रहे हैं। सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने जबालिया को घेर लिया है। इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करने का भी ताजा आदेश जारी किया है जो युद्ध के शुरुआती हफ्तों में काफी हद तक खाली हो गया जब इजराइल ने उत्तरी गाजा की पूरी आबादी को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया था। ऐसा अनुमान है कि कठिन परिस्थितियों और बड़े पैमाने पर विनाश के बावजूद 3,00,000 लोग वहां रह रहे हैं। सेना ने इलाके में गिराए पर्चों में कहा, 'हम युद्ध के नए चरण में हैं। इन इलाकों को खतरनाक युद्ध क्षेत्र माना जाता है।' फलस्तीनी निवासियों ने उत्तरी गाजा में इजराइल की ओर से भारी बमबारी किये जाने की खबर दी है। स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि जबालिया में एक घर पर बमबारी में उनका एक सहकर्मी हसन हम्द मारा गया। फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन ताजा हमलों से गाजा में मारे गए फलस्तीनियों की संख्या अब 42,000 के करीब पहुंच गयी है। मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि इनमें से कितने आम नागरिक और आतंकवादी हैं, लेकिन मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यह हमला रविवार तड़के किया गया। इससे पहले इजराइल ने शनिवार को लेबनान में बमबारी करते हुए हिजबुल्ला और हमास, दोनों के लड़ाकों को निशाना बनाया। लेबनान में फलस्तीनी शरणार्थियों सहित हजारों लोगों का क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के कारण पलायन जारी है जबकि गाजा में युद्ध शुरू होने के एक साल पूरे होने के मद्देनजर दुनिया भर में रैलियां आयोजित की गईं। शनिवार को जोरदार विस्फोट आधी रात के करीब शुरू हुए।

16 साल से बंधक महिला का रेस्क्यू

वजन 35 किलो रह गया, पति ने बताया मानसिक रोगी; पुलिस बोली-देर होती तो नहीं बचती

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कोलीपुरा बरखेड़ी इलाके से पुलिस ने 16 साल से कैद एक विवाहित महिला को रेस्क्यू किया है। पुलिस को मामले में पीड़िता के पिता ने शनिवार शाम 4 बजे सूचना दी थी। महिला थाना पुलिस ने जहांगीराबाद पुलिस की मदद से कोली मोहल्ले के एक घर से बेहद गंभीर हालत में महिला को रेस्क्यू किया।

फिलहाल वह कुछ भी बोलने या बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस का कहना है कि हालत ठीक होने के बाद बयान लिए जाएंगे। उसके बाद पति समेत ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल डीसीपी, जोन-1 रश्मि दुबे के मुताबिक अगर कुछ दिन और देर होती तो महिला की मौत हो जाती। उसका वजन भी महज 35 किलो रह गया है।

मीडिया पीड़ित महिला के ससुराल पहुंचा। यहां बातचीत में पति और ससुर ने पीड़िता को मानसिक रोगी बताते हुए उसका इलाज चलने की बात कही है। हालांकि परिवार इलाज के पर्चे नहीं दिखा सका। पीड़िता के पति ने बंधक बनाकर रखने की बात से इनकार किया। उसने कहा- चार दिन पहले ही साले और रिश्ते की एक साली ने पत्नी से मुलाकात की थी। अगर बंधक बनाकर रखते तो उनसे मुलाकात क्यों करने देते। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर

के पुराने घर के ठीक सामने स्थित गली में पीड़ित महिला का मकान है। अंदर जाने का रास्ता इतना संकरा है कि एक आदमी भी बमुश्किल निकल पाता है। अंधेरे घर में दूसरे फ्लोर पर स्थित कमरे में महिला को बंधक बनाकर रखा गया था। इस कमरे में दिन में भी बगैर लाइट जलाए रोशन नहीं पहुंचती है।

2006 में हुई थी शादी, 2 साल बाद मिलना बंद कराया: दरअसल, महिला थाने में नरसिंहपुर के किशन लाल साहू ने आवेदन दिया था। किशन लाल के अनुसार उनकी बेटी रानू साहू का विवाह 2006 में भोपाल निवासी योगेंद्र साहू से हुआ था। साल 2008 के बाद से बेटी के ससुराल वालों ने उससे मिलने नहीं दिया। बेटी के बच्चों को भी उससे दूर भेज दिया गया। ससुराल पक्ष के प्रताड़ित करने के बाद से बेटी की हालत खराब होने की जानकारी पड़ोसियों से मिली। किशन लाल ने पुलिस से बेटी रानू को रेस्क्यू कर इलाज कराने और ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। इसके बाद महिला थाना पुलिस ने लोकल थाने की मदद से रानू को रेस्क्यू किया।

भाई बोला- वीडियो पर बहन को देखा, तब आए: पीड़िता रानू साहू के छोटे भाई शिव कुमार साहू ने बताया कि बहन को ससुराल में बंधक बनाकर रखा गया था। दो दिन पहले बहन उससे मिलने गई। हमें किसी ने सूचना दी थी की रानू को बंधक बनाकर रखा गया है। इसी सूचना के बाद बहन को भेजा था। उसने वीडियो बनाकर भेजा। तब बहन की हालत देखी और पुलिस को साथ लेकर गए। ससुराल से उसे मुक्त कराया।

उसकी हालत बेहद खराब है। वजन मात्र 35 किलो बचा है। उसके साथ अत्याचार किया जा रहा था। इस कारण उसकी हालत ऐसी हुई है। ससुराल वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

मामाजी की जयंती पर विशेष व्याख्यान आज

भोपाल (नप्र)। पत्रकारिता में राष्ट्रीय स्वरों को मजबूती देने वाले पत्रकार, संपादक, लेखक एवं विचारक मामाजी

माणिकचन्द्र वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर संवाद चर्चा का आयोजन 7 अक्टूबर को शाम 6 बजे से शिवाजी नगर स्थित विश्व संवाद केंद्र में किया जाएगा। मामाजी की 105वीं जयंती के अवसर पर 'पत्रकारिता और अपेक्षाएं : वर्तमान परिप्रेक्ष्य' विषय पर साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे एवं वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व संवाद केंद्र मध्यप्रदेश के अध्यक्ष लाजपत आहूजा करेंगे। इस अवसर पर शहर के प्रबुद्धजन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पद्मश्री अवार्डी श्रीमती दुर्गाबाई से की भेंट

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पद्मश्री अवार्डी श्रीमती दुर्गाबाई के कोटरा सुल्तानाबाद स्थित निवास पहुंचकर उनसे भेंट की तथा कुशल क्षेम पूछी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर श्रीमती दुर्गाबाई का अभिवादन किया। श्रीमती दुर्गाबाई ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का तिलक कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीमती दुर्गाबाई से लोक कला विशेषकर गोंड चित्रकारी में हो रहे नवाचारों और प्रदेश में नई पीढ़ी के कलाकारों के प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन के संबंध में चर्चा भी की। उल्लेखनीय है कि श्रीमती दुर्गाबाई को चित्रकला के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

बुधनी में अरुण यादव, विजयपुर में अशोक सिंह संभालेंगे मोर्चा

- **आईसीसी ने 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए बनाई कमेटियां**

भोपाल (नप्र)। मप्र में दो विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होना है। संभावना है कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही एमपी की इन दो सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके पहले कांग्रेस इन सीटों पर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से मप्र के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेन्द्र सिंह ने दोनों विधानसभाओं के लिए नेताओं की कमेटियां बनाई हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा के लिए बनाई गई कमेटी में राज्यसभा सांसद अशोक सिंह को संयोजक बनाया गया है। पूर्व मंत्री व विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव और पूर्व विधायक नीटू सिकरवार को इसमें सदस्य बनाया गया है।

एक्ट्रेस मेधाशंकर और क्रिकेटर यश ठाकुर ने किए महाकाल दर्शन

- **भस्म आरती में हुए शामिल; '12वीं फेल' फेम मेधा शंकर बोली- यहां दर्शन एक अलग अनुभव**

उज्जैन (नप्र)। बॉलीवुड फिल्म '12वीं फेल' फेम एक्ट्रेस मेधा शंकर और क्रिकेटर यश ठाकुर रविवार सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। दोनों ने नंदी हॉल में बैठकर महाकाल का आशीर्वाद लिया। आरती के बाद अभिनेत्री मेधा शंकर ने कहा कि- भगवान महाकाल की भस्म आरती में पहली बार आई हूं। भस्म आरती के दौरान अच्छा लगा एक अलग ही अनुभव रहा है। मेधा शंकर ने कई फिल्में की है। साल 2023 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 12वीं फेल चर्चा में रही है। एक्ट्रेस मेधा शंकर ने नंदी हॉल में बैठकर महाकाल की पूजा अर्चना की। क्रिकेटर यश ठाकुर ने कहा कि वे भी पहली बार भस्म आरती के दर्शन करने आए है। भगवान महाकाल से कामना की है कि जल्द ही भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होकर भारत के लिए खेलें। क्रिकेटर यश ठाकुर आईपीएल 2024 में पांच विकेट लेने वाले सातवें भारतीय अनकैप्ड बने थे। इसके पहले यश ठाकुर विजय हजारे ट्राफी, रणजी ट्राफी और सैयद मुश्ताक अली ट्राफी के लिए भी खेल चुके हैं।

डामर क्वॉलिटी वाला नहीं, इसलिए सड़कें खराब होती हैं

भोपाल निगम अध्यक्ष बोले- आईओ-बीपीसीएल से डामर खरीदेंगे तो ही बिल पास करेंगे; फैसला जल्द

भोपाल (नप्र)। भोपाल में जर्जर सड़कों के मुद्दे पर नगर निगम बड़ा फैसला ले सकता है। सड़कों को सुधारने या नई बनाने के लिए यदि कोई कांट्रैक्टर प्राइवेट कंपनी से डामर खरीदता है तो उसका बिल पास नहीं होगा। उन्हें इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से ही डामर खरीदना पड़ेगा। इस पर जल्द मुहर लग सकती है। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया, हर बारिश के दौरान डामर की सड़कें अक्सर खराब हो जाती हैं, क्योंकि डामर अच्छी क्वॉलिटी का नहीं होता है। अच्छी गुणवत्ता का जब डामर इस्तेमाल किया जाएगा तो सड़कें भी अच्छी बनेगी और जनता के पैसे का सही सदुपयोग हो सकेगा।

लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा

अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा, डामर की सड़कें गुणवत्ता युक्त हो, इसलिए कुछ शर्तों में हम बदलाव करने के लिए विचार कर रहे हैं। कांट्रैक्टर अब भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के बिल सबमिट करेगा तो ही बिल का भुगतान होगा। इस फैसला इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता का डामर उपयोग करने से सड़कें भी अच्छी बनेगी। लोगों को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा।

भोपाल में निगम की 4 हजार किमी सड़कें: भोपाल में नगर निगम की कुल 4 हजार किमी सड़कें हैं। इनमें से 3 हजार किमी से ज्यादा सड़कें डामर की है। होशंगाबाद रोड, एमपी नगर समेत कई बड़े इलाकों में ये सड़कें हैं। बारिश में सड़कें खराब हो जाती है। इस कारण लगातार चार महीने तक लाखों लोगों को परेशान होना पड़ता है। बारिश थमने के बाद इन सड़कों की मरम्मत निगम करवाएगा। अध्यक्ष सूर्यवंशी ने बताया, जो सड़कें गारंटी पीरियड की है, उन्हें ठेकेदार से ठीक करवाएंगे। बाकी सड़कों की रिपेयरिंग भी शुरू करवा दी गई है।

निगम की 4 हजार किमी से ज्यादा सड़कें

चीफ इंजीनियर मस्के ने बताया कि नगर निगम की सड़कों की तुलना में पीडब्ल्यूडी की सड़कें काफी कम है। निगम की 4 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की सड़कें हैं।

पीडब्ल्यूडी भी सड़कें सुधरवा रहा: पीडब्ल्यूडी की कुल 268 सड़कें 573 किलोमीटर है। इनमें से अभी 400 किमी सड़कें परफॉर्मेंस गारंटी में है। बारिश थमने के दौरान विभाग ने सड़कों की मरम्मत शुरू करवा दी थी। अभी भी मरम्मत जारी है।

डंपर ने युवक को कुचला, मौत

आरोपी चालाक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना घेरा, हाईवे पर प्रदर्शन

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अयोध्या नगर थाने के नजदीक शनिवार रात को एक डंपर ने एक्टिवा सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। रविवार सुबह बॉडी का पीएम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। दोपहर को परिजनों ने बॉडी को अयोध्या चौराहे पर रख कर आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी चालक को पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया है। जानकारी के अनुसार आकाश पुत्र कैलाश गुजराती (18) एच सेक्टर अयोध्या नगर अपने दोस्त के साथ रात करीब 11 बजे एक्टिवा से घर जा रहा था। आकाश एक वाशिंग सेंटर पर काम करता था। अयोध्या थाने के नजदीक एक्टिवा को मिट्टी से भरे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे पीछे बैठे आकाश की मौत हो गई। मृतक इकलौता बेटा था। मृतक के पिता कैलाश ने बताया कि हादसे के बाद पास में मौजूद डायल 100 ने पीछा कर आरोपी चालक को पकड़ लिया था। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

आकाश, मृतक

आरोप घायल को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया: स्थानीय रहवासियों ने बताया कि हादसे के बाद घायल नीतेश को पुलिस वाहन से अस्पताल तक नहीं पहुंचाया गया था। बाद में उसे अस्पताल पहुंचाया। आरोपी चालक को मौके से ही पकड़ लिया था, इसके बाद भी चालक को छोड़ दिया। घटना के सूचना मिलने पर कांग्रेस नेता रविंद्र साहू झूमरवाला भी मौके पर पहुंचे। अयोध्यानगर एसीपी और टीआई से बात कर डंपर मालिक एवं ड्राइवर पर एफआईआर कर गिरफ्तारी की मांग की।

मामा ने बोला पुलिस ने दिया क्रिया करम का पैसा: रविवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस समझाइश देने पहुंची थी। मृतक के मामा संजय ने बताया कि क्रिया-कर्म के लिए 25 हजार रुपए मिले हैं। हम उचित मुआवजा दिलाने और आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं।

थाना प्रभारी बोले आरोपी चालक को हिरासत में लिया: अयोध्या नगर थाना प्रभारी महेश लिल्हारे ने बताया कि आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। डंपर को भी जब्त कर थाने में खड़ा कर लिया गया है। आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है।

पॉलीटेक्निक इलाके में हादसे में महिला की मौत

- **एक गंभीर घायल, सड़क पार करते समय हुआ हादसा**

भोपाल (नप्र)। भोपाल में सड़क हादसे में एक महिला रजिया (42) की मौत हो गई। वहीं एक महिला शाजिया (38) घायल है। घटना पॉलीटेक्निक चौराहे पर स्थित हिंदी भवन की है। दोनों महिलाओं को सड़क पार करने के दौरान कार ने टक्कर मार दी। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। वहीं ड्राइवर अभी फरार बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार शाजिया पीर गेट स्थित चिरायु अस्पताल में भर्ती है, शाजिया की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं रजिया की हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। श्यामला हिल्स पुलिस के अनुसार घटना शाम 6:45 की है, जब दोनों महिलाएं सड़क पार कर रहीं थीं। यह दोनों बहनें एशबाग इलाके में रहती हैं, दोनों गृहिणी हैं। पुलिस का कहना है कि यह दोनों महिलाएं कहां जा रहीं थीं इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, घटना की जानकारी जुटाई जा रही है।

क्रिकेट खेलते समय 15 साल के लड़के की मौत

आगर-मालवा में दोस्तों के साथ खेलते समय बिगड़ी तबीयत, कार्डियक अरेस्ट की आशंका

आगर मालवा (नप्र)। आगर मालवा जिले के सुसनेर में रविवार को सुबह करीब 10 बजे क्रिकेट मैच खेलने के दौरान एक 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल के पास क्रिकेट खेल रहा था। इस दौरान उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे गंभीर अवस्था में उसके साथ खेल रहे बच्चे सुसनेर के सिविल हॉस्पिटल लेकर गए। जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी केसर राजपूत ने बताया कि माखन पिता बनेसिंह निवासी धतुरिया सुसनेर अपने दोस्तों के साथ हायर सेकंडरी स्कूल के पास क्रिकेट खेल रहा था। खेलने के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह खेलते-खेलते अचानक जमीन पर लेट गया। गंभीर अवस्था में साथ खेल रहे बच्चे सुसनेर के सिविल हॉस्पिटल ले कर गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे की मौत

माखन, मृतक

ग्राउंड पर ही हो गई थी। थाना प्रभारी केसर राजपूत ने बताया कि सुसनेर के सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पैनल ने परिजनों के कहने पर बालक का पोस्टमार्टम किया। जिसके बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। फिलहाल, सुसनेर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का पता चल पाएगा।

कार्डियक अरेस्ट की आशंका

मृतक माखन का पोस्टमार्टम करने वाले पैनल में शामिल डॉक्टर अखिलेश बागी का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत होना लग रहा है। हेड इंज्यूरी नहीं दिखाई दी है और न शरीर पर अन्य चोट के निशान दिखाई दिए है। विसरा जांच के लिए दे दिया है।

संपादकीय

पत्रकार प्रताड़ना पर सुको की फटकार

सरकार की आलोचना पर पत्रकारों पर केस दर्ज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सही फटकार लगाई है। यूपी के एक पत्रकार अभिषेक उपाध्याय द्वारा उनके खिलाफ उप्र सरकार द्वारा दायर एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि किसी पत्रकार के लिखे हुए को सरकार की आलोचना माना जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में विचार व्यक्त करने की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद-19(1)(ए) के तहत पत्रकारों के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं।

पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ यूपी के सामान्य प्रशासन के जातिगत झुकाव पर एक खबर प्रकाशित करने को लेकर दर्ज की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्वतंत्र पत्रकार होने का दावा करने वाले पंकज कुमार नाम के एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक पदों के लिए एक विशेष जाति के लोगों को तरजीह देने के बारे में खबर लिखने के लिए लखनऊ के हजरतगंज थाने में उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस संबंध में याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा कि इस बीच खबर के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा, 'लोकतांत्रिक देशों में अपने विचार रखने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उक्त एफआईआर से किसी अपराध पता नहीं चलता। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को निशाना बनाया जा रहा है। इसे सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करने के बाद से कई अन्य एफआईआर भी दर्ज हो सकती हैं। अपनी याचिका में अभिषेक उपाध्याय ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ एफआईआर राज्य के कानून प्रवर्तन तंत्र के दुरुपयोग की कोशिश है, ताकि उनकी आवाज दबाई जा सके। लिहाजा और उत्पीड़न रोकने के लिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। उनकी 'यादव राज बनाम ठाकुर राज' शीर्षक वाली रिपोर्ट के बाद 20 सितंबर को उनके विरुद्ध लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। अभिषेक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (2) 197 (1) (सी), 356 (2) (मानहानि), तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह कड़वी सच्चाई है कि सरकार के खिलाफ मीडिया में कुछ भी लिखना और बोलना अब सरकार की आलोचना माना जाता है। ऐसे पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह तक के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। साल 2022 में देश में कम से कम 194 पत्रकारों को निशाना बनाया गया। 'राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप' की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में पूरे भारत में सात महिला पत्रकारों सहित कुल 194 पत्रकारों को निशाना बनाया गया था, जिनमें सर्वाधिक कश्मीर के थे। कम से कम 103 पत्रकारों को सरकारों ने निशाना बनाया जबकि 91 राजनीतिक कार्यकर्ताओं समेत गैर-सरकारी तत्वों के निशाने पर रहे। पत्रकारों को इस तरह निशाना बनाने के मामले में कोई भी सरकार अपवाद नहीं है। दरअसल सत्ता सुख भोगने वाली कोई भी सरकार अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। झूठ तो छोड़िए, वो सच भी नहीं सुनना चाहती। उल्टे मीडिया से उनकी अपेक्षा यही रहती है कि वह सरकारों द्वारा बुने भ्रम जाल की वाहवाही करते रहें। जो सरकार की मर्जी के खिलाफ सच लिखेगा, वह प्रताड़ित होगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार से शायद इस पर कुछ अंकुश लगे।

कोलकाता के अस्पताल की घटना के मायने

नजरिया

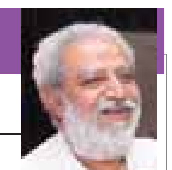

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी चिंतक हैं।

पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों जो आर जी कर अस्पताल में एक डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार और हत्या हुई, उसकी निंदा हम सभी और समूचे देश ने की। एक डॉक्टर ड्यूटी पर हो और अपराधियों के मनोबल इतने बढ़े हों कि वे अस्पताल क्षेत्र में जाकर डॉक्टर के साथ बलात्कार करें और हत्या करें, इसकी यह निसंदेह प्रशासनिक व्यवस्था की असफलता है। यह समूची राजनीतिक व्यवस्था और व्यापक अर्थ में संपूर्ण समाज के लिए एक चुनौती है। इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस कांड के विरोध में समूचे देश में हड़ताल रखी। कई दिन तक सारे देश के सरकारी अस्पतालों में मरीज भटकते रहे और इलाज के लिए वे परेशान होते रहे। कितने ही लोगों की मृत्यु इलाज के अभाव में हो गई। हालांकि तीन चार दिन बाद आईएमए ने हड़ताल वापस ले ली। परंतु पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 19 सितंबर 42 दिन तक चलती रही। इस बीच कई ऐसी घटनाएँ हुई थीं जिनको लेकर आमजन की यह समझ बनी कि अब जूनियर डॉक्टर हड़ताल वापस ले लेंगे।

इस कांड की जांच कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी। यह सुविदित तथ्य है कि सीबीआई पर कोई नियंत्रण ममता बनर्जी सरकार का नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट की मानें तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को तोते की भूमिका से बाहर निकलना चाहिए। यह भी सब जानते हैं कि सीबीआई के तोते का पिंजड़ा केंद्र सरकार के पास है। यानी अगर सीबीआई कोई पक्षपात करेगी तो भाजपा के पक्ष में हो सकता है। और यह सिद्ध भी हुआ, जब सीबीआई ने मुकदमे को बंगाल राज्य से बाहर सुनवाई हेतु भेजने का आवेदन लगाया, जिसे न केवल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया बल्कि सीबीआई को फटकार भी लगाई कि यह तो देश की पूरी न्यायपालिकाओं को आरोपित करने जैसा है। स्वाभाविक है कि, यह आवेदन सीबीआई अपने आप तो नहीं लगा सकती। कहीं न कहीं किसी न किसी का इशारा होगा। सीबीआई की जांच के बाद, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब कोर्ट की ओर से दो निर्देश दिए गए।

पहला तो यह कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जूनियर डॉक्टरों से बात करें। दूसरा यह कि अगर दस सितंबर की शाम तक जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आते हैं तो उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो। यह आम उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आयेंगे। परंतु उन्होंने काम पर लौटने से इनकार कर दिया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत स्पष्ट नहीं था और एक प्रकार से गेंद को ममता बनर्जी के पाले में फेंकने वाला था। अगर ममता बनर्जी दस सितंबर को हड़ताप वापस कर न आने वाले जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करती तो न केवल आंदोलनकारियों को शिकायत का अवसर मिलता बल्कि यह आग में घी डालने जैसा होता। अच्छा तो यह होता कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आदेश देता कि जब डॉक्टरों की सारी मांगें मान ली गयी हैं या मानने को सरकार तैयार है तो फिर हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए डॉक्टरों को काम पर वापस आना चाहिए।

दूसरे निर्देश के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों को बातचीत के लिए एक 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बुलाया। इस पर भी जूनियर डॉक्टरों का रवैया तार्किक नहीं था। एक तो पहले उन्होंने कहा कि संख्या निर्धारित नहीं की जाये, सभी लोग आयेंगे तथा बातचीत का लाइव टेलीकास्ट हो।

ये दोनों ही शर्तें न केवल आश्चर्यजनक थीं बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि शायद बातचीत न करने का बहाना खोजने की थीं। बाद में तीस की संख्या पर वे सहमत हुए, परंतु लाइव टेलीकास्ट की मांग पर अड़े रहे।

आपसी बातचीत की चर्चा के लाइव टेलीकास्ट का क्या औचित्य था? ऐसा लगता है कि यह भी एक योजना थी कि कुछ उत्तेजक और अपमानजनक बातें कही जायें जो देश में प्रचारित हों। सारे देश ने मीडिया में ममता बनर्जी की वह फोटो देखी है जहां वे खाली कुर्सियों के सामने अकेले बैठी, तीन घंटे तक इंतजार करती रहीं, पर डॉक्टर नहीं आये।

मुख्य सचिव और डीजीपी ने भी डॉक्टरों को बातचीत के लिए प्रेरित करने के प्रयास किये परंतु वे सफल नहीं हुए। चूंकि आमतौर पर आम लोग बगैर कानूनी प्रक्रिया को समझे यह मांग करते हैं कि बलात्कारी को फांसी दी जाये। ऐसे समाचार जब मीडिया में आते हैं तो आमजन को खुशी भी होती है। वे भूल जाते हैं कि दंड देने की एक वैधानिक प्रक्रिया है। बलात्कार या हत्या करने वाले को मृत्युदंड देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, परंतु न्यायपालिका ने फांसी के लिए यह सिद्धांत तय किया है कि बलात्कारी या हत्यारे को तभी फांसी दी जाये जब यह घटना श्रेयर आफद रेयरेस्ट्य हो। आमजन को यह भी पता नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दिए जाने पर भी राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग कई बार राष्ट्रपतियों ने किया भी है।

भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने तब उन्होंने क्षमादान याचिकाओं को बड़ी संख्या में निरस्त किया था। लंबे समय से प्रतीक्षारत अपराधियों को फांसी दिलाई थी। हालांकि एक प्रकरण तब भी आश्चर्यजनक था। पश्चिम बंगाल में एक नाबलिग की बलात्कार के बाद क्रूर हत्या हुई थी। उसे स्व. प्रणब मुखर्जी ने क्षमादान दिया था। अनेक लोगों ने यह संदेह व्यक्त किया था कि चूंकि वह बंगाली ब्राह्मण था इसलिए क्षमादान दिया गया। अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। प्रणब बाबू ने अपनी छवि को बचाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाकर यह कानून पारित कराया था कि हत्यारे बलात्कारी को फांसी का ही दंड दिया जायेगा। यह आश्चर्यजनक सत्य है कि केंद्र सरकार द्वारा नामित पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को स्वीकृति देने के बजाय राष्ट्रपति को प्रेषित किया है। इसका क्या औचित्य है, यह आम समझ से परे है। इस पर भी जन-चर्चा यही है कि यदि राज्यपाल महोदय स्वीकृति देते तो यह ममता बनर्जी के पक्ष में होता। अगर अस्वीकृत करते तो भाजपा के खिलाफ जाता। इसलिए प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजकर अपने आपको जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया। राष्ट्रपति महोदय ने इस कानून के प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया, परंतु सार्वजनिक रूप से यह बयान जरूर दिया कि वे बहुत व्यथित हैं।

राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के शीर्ष पद पर हैं, महिला हैं, माँ हैं, इसलिए व्यथित होना स्वाभाविक है। परंतु आम जनमानस में यह प्रश्न तैर रहा है कि बिहार में बलात्कार की कई घटनाएँ हुईं, महाराष्ट्र में हुईं, उज्जैन के महाकाल लोक में वे पूजा-अर्चना करने गयी थीं, वहां सार्वजनिक स्थल पर बलात्कार की घटना हुई। भोपाल में एक महिला मरीज के साथ डयूटी पर तैनात डॉक्टर ने छेड़खानी की। उड़ीसा में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में बेटियों के साथ घटनायें हुई हैं और ऐसी अनेक घटनाएं हाल में घटी हैं, उन पर राष्ट्रपति जी ने व्यथित होने का बयान क्यों नहीं दिया? मैं मानता हूँ कि राष्ट्रपति जी की कोई दुर्भावना नहीं रही होगी बल्कि शायद भारत सरकार के गृहमंत्रालय ने विधिवत प्रक्रिया से इस घटनाओं से उन्हें अवगत नहीं कराया होगा।

जूनियर डॉक्टरों की इस लंबी हड़ताल के दौरान मीडिया के अनुसार लगभग 27 मरीजों की मौत हो गई। हो सकता है कि यह संख्या ज्यादा भी हो, क्योंकि अमूमन कस्बाई घटनाएं मीडिया में स्थान नहीं पा पाती है।

जनमानस में एक प्रश्न और भी है कि आईएमए ने उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जिनमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या आपराधिक कृत्यों में डॉक्टरों के नाम आये। अपवाद को यदि छोड़ दें तो नियमों के बावजूद सारे देश में अधिकांश डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और अथाह पैसा कमा रहे हैं। आईएमए के चेयरमैन रहे गुजरात के एक डॉक्टर के पास से काफी धनराशि पकड़ी गई जिसे वे मेडिकल कॉलेजों की मान्यता देने के एवज में लेते थे। इस पर आईएमए ने कभी कोई पड़ताल नहीं की।

डॉक्टर मित्र भी हमारे समाज और परिवार के होते हैं। उनका भी राष्ट्रीय दायित्व होता है। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों के बातचीत पर न आने के बाद ममता बनर्जी ने बहुत दुखी होकर कहा था कि अगर जनता चाहती है तो वे इस्तीफा देने को तैयार हैं।

पश्चिम बंगाल के जनमत का एक बड़ा हिस्सा अब ये मानने लगा है कि आर जी कर बलात्कार मामले के बाद देश की सरकारी पार्टी व अन्य बड़े राजनीतिक दलों यहां तक कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों की मंशा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता व प्रतिशोध के चलते ममता बनर्जी को अपराधी सिद्ध करने व अपदस्थ करने की है। इसलिए भाजपा शासित प्रदेशों व कांग्रेस शासित प्रदेशों में हुई बलात्कार व हत्याओं की घटना को केंद्र सरकार से लेकर बड़े राजनीतिक दल, उनका नियंत्रित मीडिया और आईएमए भी नजर अंदाज कर रहा है। राजनीतिक विरोध होता है, होना चाहिए, परंतु जिस प्रकार ममता बनर्जी को चहुंओर से घेरकर लांछित किया जा रहा है वह न्यायसंगत नहीं लगता।

अच्छा हो कि राष्ट्रपति महोदय या सर्वोच्च न्यायालय या केंद्र की भाजपा सरकार व कांग्रेस पार्टी यह संविधान संशोधन करा दे कि यदि किसी भी राज्य में हत्या सह बलात्कार की घटना होगी तो वहां के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार माना जायेगा। यद्यपि यह एक गलत कानून होगा, परंतु कम से कम बराबरी से तो लागू होगा।

देश के मीडिया में सुश्री ममता बनर्जी के प्रति एक छिपी हुई अरुचि या घृणा है। उसके कारण राजनीतिक भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं और आर्थिक भी।

21 सितंबर के एक दैनिक अखबार में एक खबर छपी है जिसका शीर्षक है- श्ममता के घर से 19 हजार करोड़ का निवेश लाये मोहन्य। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादस बीस सितंबर को कोलकाता के इंडस्ट्री मीट में शामिल हुये थे। यह खबर है कि सोलह बड़े उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में निवेश की सहमति जताई। उद्योगपति अमूमन किसी सूबे का नहीं होता। क्या टाटा को गुजरात, महाराष्ट्र या झारखंड का कहा जायेगा? उद्योगपति तो अपनी मुनाफे की संभावना को देखकर उद्योग लगाता है। कोई मुख्यमंत्री पीले चावल देने जाये न जाये अगर उसे लाभ मिलेगा तो पूंजी निवेश करेगा। पर इस खबर से ऐसा लगता है जैसे, उद्योगपति ये बंगाल से भाग रहे हैं। सरकार से उद्योगपति प्रशासनिक सुरक्षा अवश्य चाहता है। हालांकि उसके लिए भी उसे सरकार की मनुहार की आवश्यकता कम होती है। वह राजनीति को खरीदना चाहता है।

अंत में इतना अवश्य कहूँगा कि कोई मुख्यमंत्री यह नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में महिलाएं असुरक्षित हों। आपराधिक घटनाएं घोषित करके नहीं होतीं, वे कई बार आकस्मिक ढंग से घटती हैं। केवल किसी घटना के लिए नहीं बल्कि सरकारें अगर अपराधों को छिपाने व अपराधियों को बचाने का प्रयास करें तब ही उन्हें दोषी माना जाना चाहिये।

मैं उज्जैन में दिनदहाड़े हुए बलात्कार के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, हरियाणा में नाबालिग बच्ची के साथ हुई घटना के लिये श्री नायाब सिंह सैनी को, मुंबई की घटना के लिये शिंदे को, उड़ीसा में कैप्टिन की मंगतेर से हुई घटना को श्री मोहनचरण मांझी को दोषी नहीं मानूँगा। इसी कसौटी पर ममता बनर्जी या अन्य किसी मुख्यमंत्री को भी देखा जाना चाहिए।

भाजपा की आंतरिक स्थिति के संकेत

अनिल ठाकुर

लेखक स्तंभकार हैं।

इन दिनों बीजेपी में सत्ता , संगठन एवम मातृ संस्था के बीच एक ऐसा अंर्तद्वंद चल रहा है जो वैचारिक मतभेद से ज्यादा निजी अहम की टकराहट में बदल गया है । ऐसा पहली बार नही हुआ है , इसके पहले बलराज माधोक , कल्याण सिंह , उमा भारती के उदाहरण हमारे सामने है । अटल जी और संघ के बीच भी कई मुद्दो पर वैचारिक मतभेद उजागर भी हुए थे। लेकिन उस दौर और आज की बीजेपी में बहुत अंतर आ चुका है। ये मतभेद इतने खुलकर सामने नही आते यदि बीजेपी इस बार भी पिछले दो बार की तरह अपने बलबूते लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लेती । पिछली बार की तुलना में 63 सीटें कम होने से बीजेपी की कलह निजी अहम का रूप ले चुकी है । इस विवाद के तीन प्रमुख किरदार है, मोदी, योगी एवम एक मातृ संगठन होने के नाते संघ, जो यह मानता है कि पार्टी को उसके निर्देश के अनुसार ही चलना होंगा । भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन ऐसा ना हो कि इस बार का विवाद पार्टी को किसी बड़े विभाजन की ओर धकेल दे । इस अंदरूनी कलह का विपक्ष के नेता भी पूरा लाभ ले रहे है । कुछ दिनों पूर्व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसते हुए कहा था

अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बना बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइये... आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा - वैसे भी आपके जो हालात हैं... उसमें आप बीजेपी में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं... अलग पार्टी तो... आपको आज नहीं तो, कल बनानी ही पड़ेगी । योगी ने अपनी और से इसका जवाब दिया , लेकिन पार्टी में उनको लेकर जो बातें सामने आ रही है , उस मौके का फायदा अखिलेश उठाने से नही चूके ।

संसद में बीजेपी की सीटों की संख्या में कमी को लेकर राहुल गांधी भी अलग अलग बयानों में मोदी पर तंज कसने से नही चूकते है, लेकिन उनमें गंभीरता कम और हास्य ज्यादा नजर आता है । बीजेपी सांसदों की संख्या में कमी हो जाने के बावजूद मोदी कही कमजोर नजर नहीं आ रहे है , चाहे वह सरकार का गठन हो या साथी दलों को विभागों का आवंटन । विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के समय भी एनडीए घटक दलों को उकसाने की पूरी कोशिश की थी मगर नाकाम रहे । बजट सत्र के बाद मोदी ने पार्टी के एजेंडे के बचे हुए मुद्दो को लागू करने के लिए नए बिल लाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, चाहे वह वक्फ बोर्ड से संबंधित बिल ही क्यों न हो । 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र की अवधारणा को लेकर रेल्वे, डिफेंस या औद्योगिकरण का जो उनका लक्ष्य है उस दिशा में नीत नई योजनाएं आ रही है । लेकिन चुनावों के दौरान पार्टी अध्यक्ष के एक बयान ने कि बीजेपी अब इतनी मजबूत हो गई है कि उसे संघ की सहायता की जरूरत नही है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। यह माना गया कि यह बयान उनके इशारे पर दिया गया था। संघ ने तुरंत तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी , लेकिन संघ के एक कार्यक्रम में बोलते हुए संघ प्रमुख ने इशारों में उन्हें नसीहत दे डाली । संघ के अन्य पदाधिकारी एवम चिंतकों ने अपने बयानों एवम लेखों में भी मोदी पर निशाना साधा ।

पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने संघ प्रमुख से मिलकर सफाई भी दी थी। उम्मीद थी कि केरल में होने वाली संघ एवम पार्टी की समन्यवक बैठक में इसका कुछ उचित समाधान निकल आयेगा लेकिन उसके बाद के संघ प्रमुख के बयानों से ऐसा नहीं लगता है कि संघ इस बयान को भुला चुका है । कई अफवाहें हवा में है, फिलहाल तो इनका निराकरण होना असम्भव है । मोदी एवम संघ के बीच कई बिंदुओं पर वैचारिक मतभेद की बातें उनके गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उठी थी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए मोदी पीएम के पद तक पहुंचने में सफल हुए। अटल जी और संघ के बीच में भी कई मामलों में मतभेद थे, लेकिन अंत तक समन्वय बना रहा , मगर इस बार मोदी संघ की ओर से थोड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे है । इन सबके बावजूद मोदी की कार्यप्रणाली में कोई अंतर आया हो ऐसा नहीं लगता। मोदी जानते है कि जनता का एक बड़ा वर्ग आज भी उनका प्रशंसक है ।

यह मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि पहले जनसंघ एवम अब बीजेपी को इस मुकाम पर पहुंचाने में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । आज उसके स्वयंसेवकों की संख्या लाखों में है। देश के सुदूर इलाकों में आपदा के समय उसके स्वयं सेवक भूख प्यास की चिंता किए बिना राहत कार्य में सेवाएं देते रहते है। लेकिन संघ को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह एक सामाजिक संगठन है । आज के युग में उन्नत राष्ट्र बनने के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है , राजनीतिक दल या नेता को समयानुसार कई समझौते करना पड़ते है । बीजेपी को इस स्थिति तक लाने में संघ का योगदान है तो यह मोदी का आकर्षण एवम आम आदमी का उन पर भरोसा ही है जिसने बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत पर पहुंचाया था । मोदी ही वह व्यक्ति है जिसने संघ के एजेंडे को सफलता पूर्वक क्रियान्वित किया। क्या राम मंदिर विवाद का निराकरण एवं निर्माण इतना आसान था, क्या धारा 370 को इतनी आसानी एवम बिना किसी खून खराबे के समाप्त किया जा सकता था ? ऐसे और भी उदाहरण है लेकिन मोदी की इच्छा शक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए यह दो ही काफी है । संघ को यह समझना होंगा कि अपनी स्थापना के करीब 90 वर्षो के बाद उसके आनुषंगिक संगठन बीजेपी की 2014 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी ।

आज भी यदि विपक्ष एवम अंतराष्ट्रीय चुनौतियों का कोई सामना कर सकता है तो वह मोदी है । ऐसा नहीं है कि बीजेपी में अन्य योग्य उम्मीदवार नहीं है मगर दूसरे दलों पर आधारित एवं उनकी शर्तो पर सरकार चलाने से संघ का एजेंडा कभी पूरी तरह लागू ही नही हो पायेगा। संघ के कार्यकर्ताओं की भी अपनी निजी जिम्मेदारी एवं हित होते है, जिसे सरकार की सहायता से ही पूरा किया जा सकता है। संघ को यह भी ध्यान रखना होंगा कि बीजेपी को सही मायने में राष्ट्रीय पार्टी मोदी की रणनीति ने ही बनाया है, सिर्फ संघ या उसकी सोच से ही जुड़े ही उसके कार्यकर्ता हो ऐसा नहीं है । विभिन्न क्षेत्रों से आए युवा अपनी अलग निजी सोच रखते है ।

राजनीतिक दल होने के नाते उनकी सोच को भी स्थान देना जरुरी है । ऐसे में संघ मोदी के प्रति कोई अतिरेक कदम उठाता है तो अपना ही नुकसान करेगा । योगी के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि मोदी से नाराजगी के चलते संघ उनके पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है , क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे है कि योगी और हाईकमान के रिश्तों में बढ़ी दरार आ चुकी है , हाईकमान उन्हे मुख्यमंत्री पद पर देखना पसंद नहीं करता। लेकिन यदि कुछ ऐसा निर्णय हुआ तो यह पार्टी के लिए घातक होंगा । मोदी के बाद योगी एवं हेमंता विश्व सरमा ही ऐसे मुख्यमंत्री है जो पार्टी एजेंडे को पूरी कड़ाई से लागू कर रहे है । ऐसे में 2027 के पहले उनकी स्थिति में परिवर्तन से नुकसान ही होंगा ।

इन दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कुछ बयानों के कई मतलब निकाले जा रहे है । यदि नड्डा का बयान मोदी के इशारे पर था तो गडकरी के बयान किसके इशारे पर आ रहे है यह अंदाज लगाना कठिन नही है । मोदी, योगी एवम संघ के बीच एक ऐसा त्रिकोण बन गया है जिसमे सब एक दूसरे से जुड़े जरूर है , लेकिन तीन अलग अलग बिंदुओं पर । ऐसे में सबके हित में है कि तीनों वस्तुस्थिति को समझकर आपसी विचार विमर्श से मतभेदों को सुलझा ले , अन्यथा इस बार का विभाजन सामान्य नहीं होगा ।

पुलिस के सामने नई आपराधिक विधियों की चुनौतियां

विधि

भूपेन्द्रसिंह परिहार

लेखक अधिवक्ता हैं।

भारत में अंग्रेजों के समय से चलती आ रही तीन आपराधिक विधियों को नये संशोधित रूप में 1 जुलाई 2024 से तीनों नई संशोधित आपराधिक विधियों को लागू किया गया हैं जो क्रमशः है; भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिकझ सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेने वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। इन विधियों को विभिन्न राज्यों की पुलिस को लागू करने की एक बड़ी चुनौती है। चूंकि पुलिस व्यवस्था से संबंधित विषय संविधान में राज्यों के अधीन आता है। भारत विशाल व विभिन्नताओं भरा राष्ट्र है। अपराध की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग रहती है। वहीं वर्तमान समय में प्रोद्योगिकी, सूचना व इंटरनेट के विकास के कारण नये-नये अपराध हमारे समाज में घटित हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय पुलिस व्यवस्था को भी इन सब चुनौतियों से बड़े स्तर पर दो चार होना पड़ेगा।

पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो भारत में वर्तमान जनसंख्या के अनुसार व अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए दक्ष पुलिस बल पहले से ही बहुत कम मात्रा में है। ऐसे में आधुनिक तकनीक व इन विधियों को नागरिकों की सुरक्षा व शांति के लिए सुचारू रूप से लागू करना, वर्तमान पुलिस व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। अपराधों की प्रकृति निरंतर बदल रही है। ऐसे में नई आपराधिक विधियों को पुलिस कैसे सुचारू रूप से लागू कर पाती है, इस पर जल्दी व पूर्ण रूप से कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

पुलिस के सामने पहले से ही कई कठिनाईयां थी और ऐसे में विधि प्रवर्तन अधिकारियों को ओर महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो उनकी पहले से ही मांग वाली भूमिकाओं को और जटिल बना देंगी। इन चुनौतियों में भारी कार्यभार, कर्मचारियों की कमी, दक्ष पुलिस बल की कमी, भ्रष्टाचार, राजनेताओं का पुलिस पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव, समुदाय का विश्वास बनाने में कठिनाइयाँ, साइबर और सीमा पार अपराधों में वृद्धि शामिल है।

वैसे नई आपराधिक न्याय प्रणाली में सुगम और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रविधान किये गए हैं। लेकिन इसे पूरी तरह धरातल पर उतारने के लिए पुलिस व्यवस्था को कड़ा परिश्रम करना होगा। पूरी तरह से डिजिटल और फॉरेंसिक पर ज्यादा जोर देने वाली इस प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने में चुनौतियां अपार है। सभी थानों और न्यायालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली की सुचारू आपूर्ति, पावर बैकअप की व्यवस्था, क्राइम सीन(अपराध स्थल) से साक्ष्य जुटाने के लिए सभी जिलों में पर्याप्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तैनाती और मोबाइल फॉरेंसिक वैन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में समय लग सकता है।

नए कानूनों को समझने और उन्हें लागू करने के लिए पुलिस को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता अगले एक दो वर्ष तक निरंतर बनी रहेगी। जिसके लिए महत्वपूर्ण समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिससे मौजूदा सुविधाओं पर संभावित रूप से दबाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए: सरकार ने 3,000 अधिकारियों का एक विशेष टास्क फोर्स स्थापित किया है, जो पुलिस अधिकारियों और वकीलों को प्रशिक्षित और निर्देश दे रहा है। वहीं आम नागरिकों को भी पुलिस के द्वारा अलग अलग माध्यमों से नई आपराधिक विधियों के विषय में जागरूक करना होगा। वहीं भारत में पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत हर राज्य की पुलिस कार्यप्रणाली व व्यवस्था अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जिसका राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक असर पड़ता है।

नए कानूनों को लागू करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों, अद्यतन प्रौद्योगिकी और उन्नत बुनियादी ढांचे की मांग ज्यादा है, जिससे पुलिस विभागों के लिए वित्तीय और तार्किक चुनौतियाँ पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए: फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वैन की तैनाती और प्रबंधन तथा प्रासंगिक मामलों में अनिवार्य फोरेंसिक जाँच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता निरंतर है। आधुनिक विधि प्रवर्तन को डिजिटल साक्ष्य प्रणालियों और अपराध विश्लेषण उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कर्मियों के लिए उन्नत तकनीकों और व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए: अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर फाइलिंग में बदलाव ने पुलिस कर्मियों के लिए डिजिटल शिकायतों को प्रभावी ढंग से संसाधित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता को जन्म दिया।

इन सभी समस्याओं व चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को नए कानूनों के बारे में बढ़ती सार्वजनिक जिज्ञासाओं और भ्रम को प्रबंधित करना होगा, जिसके लिए स्पष्ट संचार और अतिरिक्त सामुदायिक आउटरीच(पहुंच) पहल की आवश्यकता होगी। विधिक गलतियों से बचने और उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को नई आपराधिक विधियों की बारीकियों में शीघ्रता से कुशल बनने की आवश्यकता है। तब कहीं जाकर नई आपराधिक विधियों का लाभ त्वरित न्याय दिलाने व शांति व्यवस्था को बनाने में मिलेगा। साथ ही इन चुनौतियों से पार पाने पर पुलिस व्यवस्था में भी एक बड़े सुधार होने की कई संभावनाएं दिख रही है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक - उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

ऐसे तो न जगाओ

व्यंग्य

डॉ. प्रदीप उपाध्याय

वे ऐसे नहीं जागते हैं और फिर वे ही क्या उनके जैसे बहुतेरे भाई-बंधु ऐसे आसानी से जागते भी नहीं हैं, उन्हें जगाना पड़ता है.ऐसे-वैसे कोई उन्हें जगा भी नहीं सकते .हां उन्हें जगाने वाला चाहिए जरूर.अब वे कैसे जागेंगे, यह देश-काल परिस्थिति पर निर्भर करता है.

कुंभकर्ण भी क्या ऐसे ही जाग जाता था.नहीं न! उसकी नींद की अपनी खुराक हुआ करती थी और जागने की अपनी.तीर्थ नगरी में तेज बारीश की वजह से महाराजवाड़ा की एक रिटेनिंग वॉल के ढह जाने पर स्थानीय प्रशासन अपनी खुराक पाकर तत्काल नींद से फिर से सो जाने के लिए जाग गया .जागने का कारण भी इसी एक घटना में छुपा था.दीवार के नीचे दबने से दो का बैकुंठवास हो गया और दो गंभीर अवस्था को प्राप्त कर गये.वैसे सामान्य रूप से यह खुराक पर्याप्त न होती किंतु क्या करें मजबूरी में उन्हें जागना पड़ा

क्योंकि मामला मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का निकल आया , तत्काल नींद टूटना ही थी अन्यथा तो जब तक मीडिया आकर ढोल-नगाड़े नहीं बजाता तब तक कुंभकर्णी नींद कहां टूटना थी. वैसे आदमी जागता ही इसीलिए है कि फिर चैन से सो सके!

कहने वाले कहते भी हैं कि ऐसी भी क्या कुंभकर्णी नींद सोना कि आसपास की कोई खबर ही न हो.लेकिन भाई सोने का भी अपना एक अंदाज़ है, एक अलग ही मजा है. कहने को तो वे कहते हैं कि नींद आती नहीं है रात-रात भर लेकिन जब नींद से जगाने की बात आती है तो कुंभकर्ण को भी ढोल-नगाड़े बजा-बजाकर जगाने के जतन करना पड़ते थे.

क्या आपको खबर है कि एक प्रदेश की राजधानी से सटे जिले के किसान अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसलों के खराब होने और समुचित भाव दिए जाने की मांग पर जिम्मेदारों को जगाने के लिए पेड़ो पर चढ़कर शंखनाद कर रहे हैं. संभव है आवाज आप तक भी पहुंची हो.अलग अलग मामलों में अलग अलग टोटके करना पड़ते हैं. यदि टोटके ना हों तो कुंभकर्णों की नींद टूटे ही नहीं.

पिछले दिनों की ही तो बात है.बेसमेंट में पानी भर आया,कुछ अभ्यर्थी शहीद हो गए और यहां-वहां बेसमेंट में बेफिक्री से चल रही कोचिंग के गले की हड्डी बन गया.आखिरकार कुंभकर्ण जाग गए और एक्शन में आ गए. कुंभकर्णी नींद में सोए जन जागना भी नहीं चाहते किंतु क्या करें!

कभी प्रकृति आड़े आ जाती है तो कभी इंसान की असावधानी या उदासीनता.कुंभकर्ण सा मानव प्रश्न भी करता है कि बैठे ठाले अतिक्रमण से संकरी हुई गलियों में आगजनी होती ही क्यों हैं, अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में अनायास विस्फोट क्यों हो जाता है,नए ब्रिज, नए पुल-पुलिया, नए बांध क्यों ढह जाते हैं, अच्छी-खासी नींद में खलल पैदा करने को.

उनके प्रश्न जायज हैं क्योंकि उनकी नींद में ये खलल पैदा करते हैं उनका सोए रहना भी समझ में आता है क्योंकि उनसे प्रश्न करने वाले और जवाब लेने वाले खुद बेफिक्री की नींद सोए हैं. कोई पांच साल में जवाब देने का अभिनय करने की मुद्रा में आ जाता है तो कोई साठ-पैसठ साल की आयु पूरी होते ही अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर गंगाघाट नहा लेता है. सवाल वहीं रहते हैं, जवाब की कहीं कोई उत्कंठा नहीं. ये भी कुंभकर्णी नींद में और हम भी कुंभकर्णी नींद में. चिल्लाने वाले चिल्लाते रहें जागो सोने वालों!

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

प्रतिभाशाली छात्र फीस के कारण प्रवेश से वंचित क्यों

यदि किसी गरीब छात्र ने फीस जमा करने के पर्याप्त प्रयास किए। लेकिन, फिर भी छात्र फीस जमा नहीं कर सका तो इस आधार पर छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर वंचित किए गए एक दलित छात्र को आईआईटी, धनबाद में प्रवेश देने का आदेश दिया।

अतुल कुमार ने अपने अंतिम प्रयास में जेईई परीक्षा उत्तीर्ण की। आईआईटी, धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक सीट आवंटित की गई। लेकिन वे समय सीमा में आवश्यक शुल्क का भुगतान नहीं कर सके। इस कारण उन्हें सीट नहीं मिली। इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आईआईटी, धनबाद को इस दलित छात्र को प्रवेश देने का निर्देश दिया, जिसने फीस जमा करने की सीमा से चूकने के बाद अपनी सीट खो दी थी। सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम इतने युवा प्रतिभाशाली छात्र को वंचित किए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने तिखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस छात्र को झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण भेजा गया। फिर वह चेन्नई कानूनी सेवाओं में गए। फिर उन्हें उच्च न्यायालय भेज दिया गया। एक दलित छात्र को एक खंभे से दूसरे खंभे तक दौड़ाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर के निवासी और एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने उच्चतम न्यायालय जाने से पहले झारखंड उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। छात्र के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसके पिता प्रतिदिन साढ़े चार सौ रूपये कमाते हैं। उन्होंने कहा कि फीस की व्यवस्था करना एक बड़ी बात है। उन्होंने (पिता) ग्रामीणों से पैसे इकट्ठा किया। इस कारण फीस जमा करने में विफल हुआ। आईआईटी, धनबाद की ओर से पेश वकील ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने अतुल कुमार को एक एसएमएस भेजा और आईआईटी ने उन्हें भुगतान पूरा करने के लिए दो व्हाट्सएप चैट भेजे। आईआईटी के वकील ने कहा कि वह हर दिन लॉग-इन करते थे। इस पर न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आप बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं खोज रहे हैं? सीट आवंटन सूचना पर्ची से पता चलता है कि आप चाहते थे कि वह भुगतान करें और अगर उसने किया, तो और कुछ नहीं चाहिए था।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि वह एक प्रतिभाशाली छात्र हैं। केवल एक चीज जिसने उसे रोका वह मात्र सत्रह हजार की राशि थी। उन्होंने कहा कि 'किसी भी बच्चे को सिर्फ इसलिए प्रवेश से वंचित नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पास प्रवेश के लिए फीस नहीं है। हमारा विचार है कि एक प्रतिभाशाली छात्र को अधर में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि आईआईटी, धनबाद में प्रवेश दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अतुल कुमार को उसी बैच में भर्ती कराया जाना चाहिए और किसी अन्य छात्र की उम्मीदवारी को बाधित किए बिना उनके लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जानी चाहिए।

न्यायाधीशों ने छात्र को शुभकामनाएं दी और कहा कि ''ऑल द बेस्ट' अच्छा करो। मुख्य न्यायाधीश ने अतुल कुमार को बधाई दी। इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने दलित छात्र के आईआईटी शुल्क मुद्दे की सहायता के लिए अनुच्छेद 142 का हवाला दिया। मूल आवंटन बैच में प्रवेश अनुदान को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता के प्रवेश में उनकी अपनी कोई गलती नहीं थी। इसने आईआईटी, धनबाद के निदेशक से अनुरोध किया कि वे याचिकाकर्ता की पहले से ही बीत चुके समय के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने की क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करें।

याचिकाकर्ता एक मेधावी छात्र है। वह अनुसूचित जाति की श्रेणी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने जेईई (एडवांस्ड) 2024 की परीक्षा में भाग लिया और अपनी श्रेणी में 145-5वीं रैंक हासिल की। उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चार साल के बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के लिए एक सीट आवंटित की गई थी। यह उसका दूसरा प्रयास था। इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए प्रवेश प्राप्त करने का अंतिम मौका था। क्योंकि प्रवेश हेतु केवल दो प्रयासों की अनुमति है। याचिकाकर्ता ने खुलासा किया है कि उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली से पूरी की। परिवार की आय गरीबी रेखा से नीचे है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शुल्क के भुगतान और दस्तावेजों को अपलोड करने सहित ऑनलाइन रिपोर्टिंग को पूरा करने की समय सीमा 24 जून 2024 को शाम 5 बजे तक थी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसके माता-पिता ने शुल्क के भुगतान के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की। शाम 4.45 बजे तक उसके भाई के खाते में फीस जमा हो गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने शाम 4.45 बजे पहले प्रतिवादी के पोर्टल पर लॉग इन किया और प्रवेश की 'फ्लोट श्रेणी' में आवेदन किया और दस्तावेज अपलोड किए। पोर्टल शाम 5 बजे बंद हो गया और उसके भुगतान की प्रक्रिया नहीं हो सकी।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने पहले संस्थान को एक ईमेल भेजा। 26 जून 2024 को आईआईटी बॉम्बे कार्यालय से जेईई (एडवांस्ड) के लिए एक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी, जिसमें उम्मीदवार को आयोजन करने वाले आईआईटी, जो कि आईआईटी मद्रास है, को पुनर्निर्देशित किया गया था। आखिरकार, इन प्रयासों का कोई फल नहीं निकला। याचिकाकर्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय कानूनी सहायता सेवा समिति का दरवाजा खटखटाया। उसे मद्रास उच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति को निर्देशित किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। लेकिन जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो उन्हें इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी गई। जिन तथ्यों का खुलासा किया गया है, वे इंगित करते हैं कि आईआईटी, धनबाद में याचिकाकर्ता को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सीट का आवंटन, याचिकाकर्ता की अनुसूचित जाति की स्थिति और वे कदम जो याचिकाकर्ता द्वारा पाठ्यक्रम के लिए सीट के आवंटन के अनुसार सभी औपचारिकताओं का पालन करने के लिए उठाए गए थे। वे तीन पहलुओं के बारे में कोई विवाद नहीं है।

विपक्षी वकील ने न्यायालय को याचिकाकर्ता का लॉग-इन विवरण प्रस्तुत किया था, जो इंगित करता है कि वह पोर्टल तक पहुँचने में मेहनती था और अपने प्रवेश की प्राप्ति को सुरक्षित करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ किया। याचिकाकर्ता ने 24 जून 2024 को 15.12 घंटे और 16.57 घंटे के बीच छह मौकों पर लॉग इन किया। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह पोर्टल में लॉग इन करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा था। यदि याचिकाकर्ता के पास सत्रह हजार पांच सौ रुपये की फीस का भुगतान करने का साधन होता तो ऐसा न करने का कोई संभावित कारण नहीं है। याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभाशाली छात्र, जो नागरिकों के हाशिए के समूह से ताल्लुक रखता है और जिसने प्रवेश सुरक्षित करने के लिए सब कुछ किया है, उसे अधर में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की पर्याप्त न्याय करने की शक्ति ठीक ऐसी स्थिति है।

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो। इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह ठहराया कि अदालत ने याचिकाकर्ता के लॉग-इन विवरण को नोट किया, जो इंगित करता है कि वह पोर्टल तक पहुंचने में मेहनती था और उसने अपने प्रवेश की प्राप्ति को सुरक्षित करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ किया। याचिकाकर्ता ने 24 जून, 2024 को छह मौकों पर लॉग इन किया।

पीठ ने तदनुसार आदेश दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उस सीट के खिलाफ आईआईटी, धनबाद में प्रवेश दिया जाना चाहिए जो उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शाखा में आवंटित की गई थी। याचिकाकर्ता को उसी बैच में भर्ती किया जाएगा जिसमें उसे आवंटन के आदेश के अनुसरण में भर्ती किया गया होगा। याचिकाकर्ता सत्रह हजार पांच सौ रुपये की फीस का भुगतान करने के लिए तैयार था, जिसका भुगतान उस समय व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है जब उसे प्रवेश दिया जाता है। यदि आवश्यक हो तो इस आदेश का पालन करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता के लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जाएगी और इसके परिणामस्वरूप किसी भी मौजूदा छात्र को परेशान नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता छात्रावास आवास और अन्य सुविधाओं के आवंटन सहित प्रवेश के सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

मेजबान की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी

किसी भी प्रयोजन से जब कोई छोटा-बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, आयोजक वर्ग यथाशक्ति आमंत्रित वर्ग की संपूर्ण सुख-सुविधा का खयाल रखा ही करता है। बावजूद इसके यह देखा गया है कि जो शख्सियत छिद्रान्वेषी मनोवृति रखा करती है, आयोजन की व्यवस्था को लेकर व्यर्थ की टीका-टिप्पणी करने से बाज नहीं आती। ऐसे में होता यह है कि जिस किसी प्रयोजन से कार्यक्रम आयोजित किया गया हो, उसकी पूर्णाहुति पश्चात आयोजक और आमंत्रित वर्ग के बीच परस्पर जीवन भर की टीस बन जाया करती है। इसलिए बेहतर हो यदि जिसने जैसी व्यवस्था दी है, हमें उनकी भावनाओं को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए।

किसी भी आयोजन को लेकर उपलब्ध कराई गई व्यवस्था से हमें तालमेल बैठाने के प्रयत्न करना चाहिए। अनेक अवसरों पर ऐसा होता है कि आयोजक वर्ग द्वारा लगाया गया पूर्वानुमान पूर्ण रूप से सही नहीं बैठता। ऐसे में स्वाभाविक रूप से व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी-बेशी हो सकती है। वैसे यह भी एक स्थापित तथ्य है कि उत्तम से उत्तम आयोजन पर भी किसी न किसी बात को लेकर छींटाकाशी कर देना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। ऐसा कोई आयोजन नहीं होता जिसमें अतिथियों की संख्या का शत-प्रतिशत सटीक पूर्वानुमान लगा लिया जाता हो। अतिथि कम भी हो सकते हैं और अपेक्षा से कहीं अधिक भी।

दरअसल सारी व्यवस्थाएं अनुमान के आधार पर रहा करती है। ऐसे में हमें परिस्थितियों के अनुरूप उपलब्ध व्यवस्थाओं को इस प्रकार समायोजित कर लेना चाहिए जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का हम भरपूर दोहन कर सकें। अक्सर देखा गया है कि अत्यंत वैभवशाली एवं पूर्ण रूप से व्यवस्थित आयोजन को भी आड़े हाथों ले लिया जाता है। और कुछ नहीं तो कभी-कभी किसी आयोजन को लेकर यह मुद्दा भी उठा दिया जाता है कि इतना सब करने की जरूरत ही क्या थी? जो और जैसा आयोजन हुआ, आखिर इतनी फिजूल खर्ची यानी कि दिखावा करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसी प्रतिक्रिया एक प्रकार से हमारे पूर्वाग्रह का परिणाम होती है।

कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि खाद्य सामग्री के स्वाद को लेकर अनावश्यक रूप से सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। जाहिर है कि इसके चलते आयोजक वर्ग की भावनाएं आहत हुआ करती है। भांति-भांति के काज-क्रियावर में भी तमाम तरह की खामियां निकाल कर आयोजक वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाई जाने लगती है। वास्तव में कुछ लोगों की कुछ ऐसी आदत रहा करती है कि अच्छे से अच्छे में भी बुरे से बुरा देखने की प्रवृत्ति के चलते बिना बात के भी बात बनाई जा सकती है। आक्रोश या भाववेश में किसी कार्यक्रम को लेकर नकारात्मक टिप्पणी के परिणाम स्वरूप परस्पर रिश्तों की आत्मीयता कहीं दूर खो जाया करती है।

हर एक आयोजन की अपनी विशिष्ट गरिमा हुआ करती है। हालांकि अनेक अवसरों पर फैशन परस्ती के चलते अनावश्यक रूप से आडंबर का फैलाव भी नजर आता है। लेकिन इसे लेकर हमें अधिक गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक आयोजन में आयोजक की व्यक्तिगत अभिरुचि के दर्शन हुआ करते हैं। हर एक की अपनी अलग पसंद होती है और अलग-अलग खयाल होता है। इसमें हमारी पसंदगी या नापसंदगी का कहीं से कहीं तक कोई सवाल ही नहीं उठाता। वैसे भी यह जरूरी नहीं है कि आप हर एक आयोजन के हिस्से में हिस्सेदारी करें। कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह की चंद लम्हों की नकारात्मक प्रतिक्रिया के बीच आपसी संबंध को दांव पर न लगाए।

विचार

विवेक कुमार मिश्र

लेखक हिंदी के प्रोफेसर हैं।

जो चांद नहीं देखा तो क्या देखा?

चांद अपनी दुनिया में मगन रहता है और चाहता है कि सब उसी की तरह मगन रहा करें । कोई इस तरह से दुःखी न हो कि वहीं अकेला संसार में दुःखी मन है । अरे ! यहां हर किसी के पास इतना दुःख है कि चर्चा की जाये तो पोथी की पोथी कम पड़ जाएं । जो नहीं है उसका क्या ? जो है वह कम थोड़े है । इसलिए चांद बराबर से यह कहता रहा है कि अपनी खुशी भर खुश रहा करो । दूसरे के सुख से दुःखी रहने वाले कभी चांद की बात नहीं समझ पाते और यूं ही हैरान परेशान होकर भ्रमण करते रहते हैं । चांद से तो यह सीखने की बात है कि हर दिन कटता रहता है , एक एक कला कम होती है पर चांद कभी दुःखी नहीं दिखा और मगन इतना कि एक दिन बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा का चांद हो जाता है । पूरे आसमान पर छा जाता है और हर किसी से कहता है कि देखो मैं आज जहां हूं वह अनंत में चल पड़ने की ज़िद का परिणाम है ।

चांद दिखता है, हां बहुत दूर से दिखता है और इतना दिखता है कि जैसे कुछ और देखना ही न हो, जो चांद नहीं देखा तो क्या देखा? यद्यपि देखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है पर चांद के आगे कोई और चांद नहीं है जिसे देखने को आंखें ढूंढ रही हों इसलिए जब जैसे जीतना भी अवसर मिले चांद से बातें करों चांद को सुनो और चांद को देखों, निहारों और इस तरह चांद से मिलों कि तुम बस चांद के ही हों और चांद के अलावा कुछ और देखा ही नहीं। यह केवल कहानी किस्से की बात भर नहीं है। चांद यथार्थ है और कल्पना से भी चांद को इस तरह रच दिया गया है कि चांद के अलावा कुछ और देखना ही न हो। इसीलिए लोग-बाग दूर से दूर तक चांद को देखने के लिए आते हैं और इस तरह देखते हैं कि जैसे चांद उनका ही हो, यह किसी को पता नहीं कि चांद तो किसी एक के लिए नहीं बना है वह तो सबके साथ सबके लिए चलता रहता है। कई बार हमारे सिर पर ही चांद आ जाता है और साथ साथ चलता है। जहां-जहां जाते वहां वहां चांद भी चला जाता है और इस तरह लोग चांद को लिए चलते हैं कि कहीं दूर न होकर उनकी मुठ्ठी में ही हों, बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई कोई तो चांद को ही लेकर बैठा है और चिल्ला रहा है कि - देखो-देखो चांद आ गया। चांद इतना करीब होता है कि पता ही नहीं चलता कि हम चांद के घर में हैं कि चांद हमारे घर में है। वह तो हमारे मन मस्तिष्क में बैठा ही रहता है । चांद की दुनिया से बाहर तो कोई जा ही नहीं पाता । चांद पर कोई जाएं न जाएं इससे भी चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता वह तो बस यूं ही अपने आप को इतना व्यस्त रखता है कि उसे कभी भी समय निकालने के लिए किसी के यहां जाना नहीं पड़ता। चांद अपनी दुनिया में मगन रहता है और चाहता है कि सब उसी की तरह मगन रहा करें। कोई इस तरह से दुःखी न हो कि वहीं अकेला संसार में दुःखी मन है। अरे! यहां हर किसी के पास इतना दुःख है कि चर्चा की जाये तो पोथी की पोथी कम पड़ जाएं। जो नहीं है उसका क्या? जो है वह कम थोड़े है। इसलिए चांद बराबर से यह कहता रहा है कि अपनी खुशी भर खुश रहा करो। दूसरे के सुख से दुःखी रहने वाले कभी चांद की बात नहीं समझ पाते और यूं ही हैरान परेशान होकर भ्रमण करते रहते हैं। चांद से तो यह सीखने की बात है कि हर दिन कटता रहता है, एक एक कला कम होती है पर चांद कभी दुःखी नहीं दिखा और मगन इतना कि एक दिन बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा का चांद हो जाता है। पूरे आसमान पर छा जाता है और हर किसी से कहता है कि देखो मैं आज जहां हूं वह अनंत में चल पड़ने की ज़िद का परिणाम है। चांद कहता है कि शून्य से आकाश में चलने की यात्रा कथा हूं। पूरा का पूरा कट जाता हूं और फिर चलते चलते एक दिन पूर्णिमा का चांद बन मन पर, आकाश पर, पृथ्वी से लेकर जल लहरियों तक सब जगह छा जाता हूं। हर कोई देखता रहता है। हैरान होता है कि अरे! देखो-देखो पूनम का चांद आ गया। यह चांद मन पर छा जाता है, इस तरह कि चांद के अलावा कुछ देखना ही न हो, कोई कहता नहीं की चांद को देखो या चांद को देखोगे तो यह मिल जायेगा या यह हो जायेगा। कोई न भी देखें तो कोई पूछने नहीं आयेगा कि आपने चांद को क्यों नहीं देखा। यह भी हो सकता है कि वर्षों वर्षों हो जाये और बहुतेरे ऐसे मिल सकते हैं कि चांद को देखा ही न हो, चांद को देखने की भला फुर्सत भी किसे है और कहां इतनी खाली जगह बची है कि आदमी भागते भागते चांद को देखें ही... अब वैसे भी चांद आपकी मुडेर पर आता ही नहीं, मुडेर पर आने के लिए मुंडेर का होना भी तो जरूरी है न ही कोई आंगन बचा है जहां चांद की अठखेलियां दिखे। अब इस तरह से चांद के दिखने और चांद के साथ चलते फिरते बतियाने वाले लोग भी नहीं मिलते न ही किसी को चांद की चिंता है कि वह कहां है कैसे है या कैसा महसूस कर रहा है पर जो भी हो चांद है तो दिलचस्प...बिना किसी लाग लपेट के कभी भी आपके सिर पर आ सकता है। अब यह आप पर है कि आप उसे अपने सिर पर ढोते हैं कि नहीं पर चांद को उगना था तो उग गया। यदि आपका सिर हो तो यह आपकी समस्या है चांद को इससे क्या ? किसका सिर मिल गया और किसका सिर नहीं मिला। लोग बड़ा खुशकिस्मत मानते हैं कि अरे इनके तो चांद आ गया। इनकी तो चांदी हो गई। अब इन्हें किस बात की दिक्कत। ये तो चांद के सहारे ही मालामाल हो गये। अब कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। चांद आप से आप समृद्धि की रेखा पर ला कर रख देते हैं, फिर बिना सोचे समझे जब हर कोई यह मानने को तैयार बैठा हो कि आप अमीर आदमी हैं तो तबियत से अमीर ही बन जाइए। वैसे भी गरीब, बेबस, थका हारा कौन दिखना चाहता वह भी नहीं दिखता जो वास्तव में गरीब गुरबा ही हो, उसे भी रह रह कर बढ़िया से रहने की हूक उठती रहती है पर जब आपके सिर पर चांद आ ही गया है तो निश्चित ही आपको अमीर हो जाना चाहिए। मन से अमीर हो ही जाइए। क्या फर्क पड़ता है अमीर हों या न हों पर अमीर हो जाने और अमीर मानने में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे भी एक न एक दिन दुनिया का चक्र बदलता है और सभी के दिन बदलते हैं तो आपके दिन जब चांद ने ही बदल दिया है तो फिर इतना क्यों सोच रहे हैं? तबियत को बेहतर कीजिए और चांद की तरह ही दूर से खिलते प्रसन्न होकर दुनिया में अपने हिस्से की खुशी तो कम से कम जीना ही चाहिए। यह कोई बड़ा काम नहीं है न ही इसमें किसी तरह का खर्च आता है। बात बस मन की प्रसन्नता का है। आप भी खुश हो गये और चांद तो चांद की तरह खुश रहता ही रहता है। चांद पर कहानी लिखने नहीं, चांद को जानने, चांद से मिलने और चांद कैसा दिखता है को जानने के लिए सब लोग चांद पर जाना चाहते हैं। कोई भी चांद को न तो भूलता है न ही भुलाना चाहता है। चांद है तो प्रीति की कथाएं भी चांद जैसी हो जाती हैं। चांद अपनी शीतलता में, अपने रागत्व में और अपने होने के अंदाज में ही इतना प्यारा है कि बस देखते रहिए अपने चांद को... दुनिया भी सुंदर दिखेगी। चांद है तो सृष्टि मात्र में सौंदर्य की लहरें उठती रहती हैं। सुंदरता में भी सौंदर्य की लहरें उठती रहती हैं । जहां ये लहरें नहीं होती वहां लाख कोशिश कर लें कुछ नहीं होने वाला है । देखना होगा कि आपके पास कितना चांद आता है और आप स्वयं चांद को कैसे लेते हैं ? चांद को वहीं जान पाता है जो चांद को करीब से देखा हो...चांद पर रहते हुए चांद की दुनिया को जाना हो ... वैसे तो सब चांद को कल्पना की आंखों से देखते रहते हैं । चांद कभी भी हमारी कथाओं और ग्रह कक्षाओं से बाहर नहीं रहा। चांद हमेशा हमारे बुलावे पर आंगन में चाय पीने भी आ जाता रहा है और न जाने कितनी बार मां लोरी सुनाते हुए चांद के आ जाने की कथा कहती रहती थी और चांद आंगन में पेड़ों की पत्तियों से झांकता हुआ आ ही जाता था। सारे बच्चे खुश होकर आकाश में चांद तारों से बातें करते, चांद की आभा को निहारते रहते, चांद का पूरा दिखना आकाश और धरती के जैसे खिल जाने की कथा ही हों। आप कितना चांद देख पाते हैं यह आपके खुशी वाले मन पर निर्भर करता है।

त्योहारों को लेकर भौंरा पुलिस चौकी में शांति समिति की बैठक संपन्न

संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों से रखी जायेगी नजर

बैतूल/भौंरा। नवरात्र और आगामी दशहरा और दीपावली पर्व पर नगर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भौंरा पुलिस चौकी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीओपी मयंक तिवारी, तहसीलदार सुनैयना ब्रम्हे, शाहपुर थाना प्रभारी जयपाल इवनाती, चौकी प्रभारी नीरज खरे एवं नगर के व्यापारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में त्योहारों के दौरान शांति, सुरक्षा और सौहार्द्र बनाए रखने पर विशेष चर्चा की गई। एसडीओपी मयंक तिवारी ने नागरिकों और व्यापारियों से कहा कि

प्रशासन की प्राथमिकता है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। त्योहारों के दौरान अतिरिक्त पुलिस गश्त और सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। तहसीलदार सुनैयना ब्रम्हे ने नागरिकों से अपील की कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। नगरवासियों और व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी से ही त्योहारों का सफल और सुरक्षित आयोजन हो सकेगा। शाहपुर थाना प्रभारी जयपाल इवनाती ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस को अलर्ट मोड में रखा जाएगा और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाएगी और यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। व्यापारियों ने प्रशासन को अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में वे पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। नागरिकों ने नगर में साफ-सफाई, सुरक्षा और यातायात की बेहतर व्यवस्था की मांग की। बैठक के समापन पर थाना प्रभारी ने कहा कि नगर में अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। प्रशासन ने सभी को भरोसा दिलाया कि त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

शाहपुर महाविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

बैतूल/शाहपुर। शाहपुर महाविद्यालय में इफेक्टिव यूस ऑफ ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर फॉर लर्निंग विषय पर एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, यह कार्यक्रम पुस्तकालय अध्यक्ष डॉ. पवन सिजोरिया की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य एमडी वाघमरे ने की। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों, विद्यार्थियों को ई-ग्रंथालय सॉफ़्टवेयर से अवगत करना एवं उसका

बेहतर उपयोग कैसे करना है, के बारे में जानकारी देना था। इस अवसर पर डॉ. पवन सिजोरिया ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से ई-ग्रंथालय सॉफ़्टवेयर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बताया कि ई-ग्रंथालय सॉफ़्टवेयर के माध्यम से पुस्तकों का आदान-प्रदान, ऑनलाइन पुस्तकों का उपयोग, घर बैठे या अन्य स्थान पर पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों को रिजर्व करना, पुस्तकालय के वेब ओपक का उपयोग, डिजिटल लाइब्रेरी का प्रयोग करना करने कि प्रक्रिया को समझाया ताकि वे वेब ओपक एवं डिजिटल पुस्तकालय का उपयोग में दक्षता प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम के माध्यम से वेब ओपक और डिजिटल लाइब्रेरी के संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर, शैक्षिक और अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को गूगल फॉर्म के माध्यम से ई-सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। कार्यशाल में महाविद्यालय के डॉ. सुभाष वर्मा, डॉ. देवेंद्र कुमार रोडगे, अमित यादव, अरविंद चौकीकर एवं विद्यार्थी सहित अन्य सभी सदस्य उपस्थित रहे।

सीढ़ियों से गिरा हेड कॉन्स्टेबल, उपचार के दौरान मौत

बैतूल। पुलिस चौकी की सीढ़ियों से गिरे हेड कॉन्स्टेबल की उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। हेड कॉन्स्टेबल घोड़ाडोंगरी की पुलिस चौकी में पदस्थ थे। घोड़ाडोंगरी पुलिस चौकी प्रभारी आम्रपाली डहाट ने बताया कि हेड कॉन्स्टेबल कुंवरलाल वरवड़े (54 वर्ष) शनिवार शाम पुलिस चौकी से पाथाखेड़ा चौकी गए थे, यहां सीढ़ियां उतरते समय वे गिर गए। चौकी में मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें तत्काल डब्ल्यूसीएल अस्पताल ले गए। यहां प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही बैतूल एसडीओपी शालिनी परस्ते ने जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की है। उनके परिजनों को वेलफेयर फंड से तात्कालिक सहायता के रूप में एक लाख रुपए की नकद राशि दी गई है।

ब्रेड फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान

बैतूल। ब्रेड फैक्ट्री में आग लगने से फैक्ट्री संचालक को लाखों का नुकसान हुआ है। घटना आठनेर के वार्ड नंबर 15 की है, जहां रिहायशी क्षेत्र दूर होने के कारण आग लगने की सूचना दूरी से लगी। रविवार सुबह जब लोगों ने फैक्ट्री से धुंआ उठता देखा, तो इसकी सूचना फैक्ट्री संचालक को दी। तत्काल फैक्ट्री संचालक और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि ब्रेड फैक्ट्री संचालक ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। संचालक शरीफ खान ने बताया कि सुबह फैक्ट्री के पास रहने वाले लोगों ने शेड से धुआं उठते देख, उन्हें सूचना दी। जब वह मौके पर पहुंचे तो आगजनी से काफी नुकसान हो चुका था। फैक्ट्री का शेड खोलने पर अंदर रखी सारी मशीनें जल चुकी थी। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रेड बनाने के लिए रखे तेल के पीपो की वजह से आग तेजी से फैली और उसने सारा सामान तेजी से जल गया। इससे करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। संचालक ने बताया कि आठ महीने पहले ही अपना मकान गिरवी रखकर लोन से संचालन शुरू किया था।

रबी फसल की सिंचाई को लेकर किसानों की बढ़ी चिंता

जिले में औसत से कम बारिश, असर: 65 डेम शत-प्रतिशत नहीं हुए लबालब

बैतूल। जिले में इस बार औसत से काफी कम बारिश हुई है। इस सीजन सामान्य औसत वर्षा 1083.9 मिमी की तुलना में मात्र 1011.0 मिमी ही बारिश हुई है। इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जल्द ही रबी फसल की तैयारी में जुटना है। यह फसल पूरी तरह से पानी पर ही निर्भर रहती है। जबकि इस बार कम वर्षा के कारण माइनर डेम के जलस्तर में भी ज्यादा अंतर नहीं आया है। यही स्थिति किसानों के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहपुर में पाठई, देशावाड़ी, मोखामाल, मोतीढाना में 75 प्रतिशत तक कम पानी आया है। भैंसदेही के डेम भी पूरे नहीं भरे हैं। 13 माइनर डेम में 0 से 50 प्रतिशत ही जल भराव हुआ है। जबकि 22 डेम में 50 से 75 प्रतिशत ही पानी आया है। यानि 35 डेम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध होगा। पानी की कमी को देखते हुए कृषि विभाग ने भी किसानों से अपील की है कि कम पानी वाली फसलों को प्राथमिकता के आधार पर बुबाई करें। जिससे किसान कम पानी की उपलब्धता में भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही अगर संभव हो सके तो स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करें। इससे पानी की बचत भी होगी और कम पानी में ही अच्छी पैदावार हो सकती है।

जिले में 93 प्रतिशत बारिश- इस सीजन जिले के तीन ब्लाकों में बारिश कम हुई है। सबसे कम बारिश आठनेर ब्लाक में दर्ज की गई। यहां औसत के 63.3 प्रतिशत यानि 686.3 मिमी ही बारिश हुई है, जबकि मुलताई में 759.5 मिमी यानि 70 प्रतिशत और प्रभातपट्टन में 890.5 मिमी यानि 82.1 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बैतूल में 982.4 मिमी, घोड़ाडोंगरी 1196.0 मिमी, चिचोली 1100.4 मिमी, शाहपुर 1116.3 मिमी, आमला 1086.0 मिमी. भैंसदेही 1043.0 मिमी और भीमपुर 1251.6 मिमी बारिश 4 अक्टूबर तक दर्ज की है। सबसे कम बारिश आठनेर क्षेत्र में हुई है। खासबात यह है कि कम बारिश वाले यह तीनों ब्लाक कृषि क्षेत्र है, जहां किसान के अधिकांश किसान जलाशयों से मिलने वाले सिंचाई के पानी पर निर्भर है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसानों में चिंता साफ नजर आ रही है।

जिले के डेम के हालात

जिले में छोटे-बड़े मिलाकर करीब 194 डेम है, जिनमें से 13 माइनर डेम में 50 फीसदी ही पानी पहुंच पाया है। इसके अलावा 51 से 75 फीसदी तक भरने वाले डेमों की संख्या 22 है। वहीं 76 से 99 प्रतिशत 30 डेम भर पाये है। 129 डेम ऐसे है, जो बारिश में शत प्रतिशत भरे है। इन डेमों के ही सहारे 87,695 हेक्टेयर में सिंचाई की जायेगी। इन डेमों से ही किसानों को एक पलेवा और दो पानी दिया जायेगा। हालांकि पानी कब दिया जाना है, इसका निर्णय जल उपभोक्ता समिति की बैठक के बाद ही होगा, लेकिन जिले के जिन ब्लाकों में बारिश कम हुई है, वहां के किसानों का कहना है कि रबी सीजन के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो फसल के उत्पादन पर असर पड़ेगा, क्योकि जिन किसानों के पास पानी के संसाधन उपलब्ध है, वह तो सिंचाई कर लेगे, लेकिन जिनके पास साधन नहीं, ऐसे किसान की खेती जलाशयों से मिलने वाले पानी पर ही निर्भर है।

इनका कहना है

जल उपभोक्ता समिति की बैठक के बाद ही पानी देने का निर्णय होगा। वैसे इस बारिश के सीजन में सभी डेम शत-प्रतिशत तक नहीं भरे है। 13 माइनर डेमों से किसानों को पलेवा के लिए पानी मिलेगा। 22 डेम से एक पलेवा और एक पानी दिया जायेगा।

- विपिन वामनकर,
ईई, जल संसाधन विभाग

भगवान राम बने दूल्हा, जनकपुरी में संपन्न हुआ सीता-राम का विवाह

श्री कृष्ण पंजाब सेवा समिति ने निकाली राम बारात, श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा से किया स्वागत

बैतूल। गंज स्थित पंजाबी कृष्ण मंदिर से बीती रात श्री कृष्ण पंजाब सेवा समिति द्वारा भगवान श्रीराम की भव्य बारात निकाली गई, जिसने पूरे शहर को धर्ममय बना दिया। भगवान राम का रूप धारण किए कलाकार बग्घी पर सवार होकर जब बारात लेकर निकले तो हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखा। शिवजी का धनुष तोड़ने के बाद भगवान राम दूल्हा बने और सीता माता से विवाह करने जनकपुरी पहुंचे। इस अवसर पर बाराती के रूप में केवल आयोजन समिति के पदाधिकारी ही नहीं, नगर के नागरिक भी शामिल हुए। रास्तेभर बारात का विभिन्न संस्थाओं और नगरवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया।

श्री कृष्ण पंजाब सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित रामलीला के पांचवें दिन श्रीराम विवाह और राम कलेवा की रस्में धूमधाम से सम्पन्न हुईं। इस अवसर पर आयोध्यापुरी (पंजाबी कृष्ण मंदिर) से श्रीराम की भव्य बारात निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं को भी सीधे तौर पर बाराती बनने का मौका मिला। इससे पहले, पंजाबी कृष्ण मंदिर परिसर में दोपहर के समय भंडारे का आयोजन किया गया। शाम को राम बारात धूमधाम से निकाली गई।

दूल्हा बने भगवान श्रीराम रथ में सवार थे और उनके साथ लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और गुरु वशिष्ठ भी शामिल थे। बारातियों के रूप में श्री कृष्ण पंजाब सेवा समिति के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और नगरवासी मौजूद थे। बैंड-बाजे की धुन पर बाराती झूमते हुए आगे बढ़े, जबकि युवा और बच्चे गरबा डांडिया करते हुए आकर्षण का केंद्र बने। बारात को देखने के लिए सड़कों और घरों के सामने बड़ी संख्या में लोग उमड़े और भगवान राम की मोहक छवि को निहारते रहे।

बारात का पूरे मार्ग पर जगह-जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। विभिन्न संस्थाओं और समाजसेवियों ने बारातियों को जलपान कराया। जब रामजी की बारात जनकपुरी (माता मंदिर पेट्रोल पंप) पहुंची, तो वहां के निवासियों और समिति पदाधिकारियों ने बारातियों का आत्मीय स्वागत किया। प्रभु श्रीराम और माता सीता का विधि-विधान के साथ विवाह सम्पन्न कराया गया, जिसमें विवाह की सभी रस्में पूरी की गईं। विवाह के पश्चात बारात वापस रामलीला मंच पर लौटी, जहां पारंपरिक विवाह रस्मों का मंचन किया गया। श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव हुआ मानो वे किसी वास्तविक विवाह समारोह में शामिल हो रहे हों।

भाजपा राज में महिलाएं असुरक्षित, कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली

बैतूल। मप्र कांग्रेस कमेटी के निर्देश व मप्र युवा कांग्रेस के आव्हान पर मध्यप्रदेश में बढ़ते अपराध एवं महिलाओं के शोषण और मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर देना जैसे जघन्य अपराध की घटना के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हेमन्त वागद्रे के नेतृत्व में बेटी बचाओ अभियान के तहत मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस की शुरुआत बाबा साहब डॉ.भीमराव अंबेडकर चौराहे से होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए लल्ली चौक पर समापन हुआ। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत वागद्रे ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के मामले

चिंताजनक हैं और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया, जिन्होंने महिला सुरक्षा के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। राहुल छत्रपाल ने कहा कि आदिवासी समुदाय की बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश सरकार को महिला सुरक्षा पर अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। समीर खान और रामू टेकाम ने कहा कि महिलाओं सुरक्षा देना बीजेपी सरकार की जिमेदारी हैं प्रदेश में इसी तरह जघन्य अपराध बढते रहे तो महिलाओ के सम्मान में युवा कांग्रेस इसी तरह सडको पर उतर कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एवं उग्र आंदोलन करती रहेंगी। विरोध जताने वालों में प्रमुख रुप से अरुण, गोठी, नवनीत मालवीय, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मोनू बड़ोनिया, कार्यवाहक अध्यक्ष प्रशांत राजपूत, ऋषि दीक्षित, गुलशन मिश्रा आदि मौजूद थे।

कोलंबो में कला प्रदर्शनी, बैतूल के कलाकार दिखाएंगे जौहर

बैतूल। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बट्टी राइड गैलरी लियोनेल वेंकट आर्ट सेंटर प्रेम सिटी प्रेमदासा मावथा में प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसमें बैतूल के कलाकार अपनी प्रदर्शनी का जौहर दिखाएंगे। यहां देश-विदेश के ख्याति नाम कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बैतूल निवासी और वर्तमान में शासकीय गीतांजलि कन्या महाविद्यालय भोपाल में फाईन आर्ट के सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. सिंह ने अपने आर्ट कलेक्शन के फोटोग्राफ कोलंबो पहले से भेजें थें जो चयनित हो चुकें हैं। डॉ. कीर्ति सिंह मध्यप्रदेश बैतूल के राष्टीय, अंतरराष्टीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। डॉ.कीर्ति सिंह ने अपनी कला के माध्यम से पशू-पक्षियों पर हो रहे अत्याचारों को दिखाया है। जिसमें समाज को पक्षियों को बचाने का संकेत देती है। जिसके तहत द बर्ड, वेकअप की थीम पर माडर्न आर्ट बनाया गया है। डॉ.कीर्ति को अभी तक 135 से भी ज्यादा राष्टीय, अंतरराष्टीय एवार्ड मिल चुके हैं। इनकी इस उपलब्धि पर जिले के कलाप्रेमियों ने बधाई दी है।

पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स का किया सम्मान

बैतूल। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन बैतूल की नियमित मासिक बैठक 5 अक्टूबर को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पेंशनर मुंशीलाल राठौर ने की। इस अवसर पर सितंबर 2024 में सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स अनिल कुमार पटने, परसराम पंवार, वासुदेव मांडवे, सुरेश भारती, हरी किशन इंगले, दिगम्बर साबले और धर्मदास बेलवंशी का सम्मान किया गया। बैठक के दौरान 90 वर्षीय वरिष्ठ पेंशनर मुंशीलाल राठौर का जन्मदिन मनाया गया। उन्हें शाल, श्रीफल और स्वागत पट्टिका द्वारा सम्मानित किया गया। बैठक में दिसंबर माह में पेंशनर्स डे के अवसर पर एक स्नेह सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया। सम्मेलन की तिथि निर्धारित की जाएगी, और इसमें विभिन्न प्रांतीय एसोसिएशनों के अध्यक्षों को आमंत्रित करने की योजना बनाई गई, ताकि सभी एक मंच पर आकर पेंशनर्स के हित में सामूहिक प्रयास कर सकें। अगली मासिक बैठक 5 नवंबर को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बडोरा स्थित विधाता भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक में एयू बैंक के प्रबंधक नीलेश नागले ने पेंशनर्स को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में रमेश कुमार वर्मा, हरी किशन इंगले, अनिल कुमार पटने, परसराम पंवार, कैलाश चंद्र मालवीय, विनोद राठौर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सचिव शिवचरण हजारे ने बताया कि 30 जून की वेतन वृद्धि से संबंधित 225 पेंशनर्स द्वारा दाखिल याचिका पर कोर्ट के आदेश पारित हो चुके हैं और किसी भी याचिका को अब तक लंबित नहीं रखा गया है। सभी याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हो चुकी है। अंत में वीरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शिवचरण हजारे द्वारा किया गया।

संस्कृति और समाज से जुड़ने का प्लेटफार्म है गरबा महोत्सव : ऋतु खण्डेलवाल

आरडी पब्लिक स्कूल में गरबा-डांडिया महोत्सव का आयोजन

बैतूल। शारदेय नवरात्रि पर्व पर जिले भर में मची गरबे की धूम के बीच आर.डी. पब्लिक स्कूल में अनंत गरबा एवं डांडिया महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। दो दिवसीय गरबा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर आर.डी. पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती ऋतु खण्डेलवाल ने कहा कि गरबा जैसे महोत्सव हमें अपनी संस्कृति एवं समाज से जुडने् के लिए अच्छा प्लेटफार्म प्रदान करते है, उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को ऐसे सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल करवाने की अपील की। नवरात्रि पर्व के अवसर पर आर.डी.पब्लिक स्कूल बैतूल में 5 एवं 6 अक्टूबर को दो दिवसीय अनंत गरबा डांडिया महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। दो दिवसीय अनंत गरबा एवं डांडिया महोत्सव में नागपुर की लाइव आर्केस्ट्रा के कलाकरों द्वारा गरबा महोत्सव में देवी गीतो की प्रस्तुति दी जा रही है। आर्केस्ट्रा के कलाकारों की प्रस्तुति पर छात्र-छात्राएं, अभिभावक सहित अन्य प्रतिभागी गरबा खेल रहे है। गरबा महोत्सव के दौरान विद्यार्थियों ने नौ देवी की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। गरबा महोत्सव के पहले दिन नर्सरी से दूसरी कक्षा के छात्र-छात्राओं ने गरबा-डांडियां का लुफ्त उठाया जबकि दूसरे दिन कक्षा तीसरी से कक्षा 12वीं के विद्यार्थी प्रतिभागी बनें।

डायरेक्टर ने गरबा कर किया उत्साहवर्धन - आर.डी. पब्लिक स्कूल बैतूल में आयोजित भव्य गरबा-डांडिया महोत्सव में लगभग सात सौ छात्र-छात्राओं और अभिभावकों ने गरबा-डांडिया प्रस्तुत किया। दो दिवसीय गरबा-डांडिया महोत्सव में लगभग दो हजार लोग शामिल हुए। आर.डी. पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती ऋतु खण्डेलवाल ने अभिभावकों एवं स्टाफ के साथ गरबा कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। स्कूल की डायरेक्टर के मार्गदर्शन में आयोजित गरबा डांडिया महोत्सव के भव्य आयोजन की अभिभावकों द्वारा मुक्तकंठ से सराहना करते हुए कहा कि आर.डी.पब्लिक स्कूल बैतूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं करियर के लिए मार्गदर्शन देने के साथ ही धर्म ,संस्कृति ,समाज और राष्ट्रीयता से जुड़ने के लिए ऐसे भव्य कार्यक्रम आयोजित करवाया जाना सराहनीय है।

देखा पढ़ा

ब्रजेश कानूनगो

पर्यटकों की खास पसंद हैं हाट बाजार

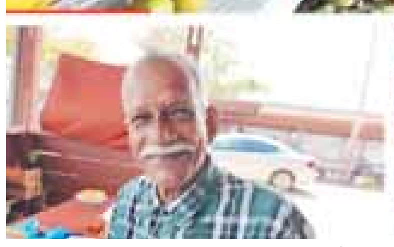

गत दिनों हमने नोमेडिक टूर व्लॉग में तोरवशु के एक यात्रा वीडियो को देखा। इसमें वह सूरीनाम देश में यात्रा कर रहे हैं। और भी कई ट्रेवलर्स और घुमक्कड़ों ने इस देश की यात्राएं की है। सुरीनाम दक्षिण अमरीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक गणराज्य है। सूरीनाम के पूर्व में फ्रेंच गुयाना और पश्चिमी गयाना स्थित है। देश की दक्षिणी सीमा ब्राज़ील और उत्तरी सीमा अंध महासागर से मिलती है। यह देश दक्षिण अमरीका में क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से सबसे छोटा संप्रभु देश है। यह पश्चिमी गोलार्ध पर एकलौता डच भाषी क्षेत्र है, जो नीदरलैंड साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा है। सूरीनाम का समाज बहुसांस्कृतिक है, जिसमें अलग-अलग जाति,भाषा और धर्म वाले लोग निवास करते हैं। बरसों पहले दक्षिणी एशिया के देशों से खासतौर से भारत से कई लोगों को मजदूरी के लिए यहां लाया गया था, वे यहां बसे तो उनकी अनेक पीढ़ियां यहां की होकर रह गईं किंतु उनमें भारत की संस्कृति, परंपराएं और भाषाएं भी बनी रहीं। यद्यपि स्थानीयता का थोड़ा प्रभाव तो बढ़ता गया।

तोरवशु के वीडियो में हम देखते हैं कि जब वे एक स्थानीय बस में बैठते हैं तो उस बस पर भारतीय देवी देवताओं के चित्र और उनके प्रति श्रद्धा के पद लिखे होते हैं। जय शिवशंकर, हर हर महादेव के अलावा बस कंपनियों के नाम भी इसी तरह के लिखे दिखाई देते हैं। इसके अलावा कई यात्री बसों के आगे बॉलीवुड के कलाकारों के चित्र भी खूबसूरती से पेंट किए नजर आते हैं। ड्राइवर और यात्री हिंदी फिल्मों के पुराने गाने तोरवशु को सुनाने लगते हैं। हमने देखा कि वहां हिंदुस्तानी लोग जो बरसों पहले भारत से गए थे उनकी संतानों में आज भी भारतीयता नजर आती है, वे लोग अपने मूल स्थान को भारत जाकर देखना चाहते हैं, जहां उनकी कभी जड़ें रही होंगी। ज्यादातर घुमक्कड़ स्थानीय बाजारों में घूमना फिरना, खरीददारी करना बहुत पसंद करते हैं। चाहे दीपांशु सांगवान हो या दावूद अखुनजादा, यह लोग वहां के स्थानीय सब्जी बाजार में अवश्य जाते हैं। दुकानदारों और ग्राहकों से दिलचस्प बातचीत करते हैं। तोरवशु भी ऐसे ही एक बाजार में घूमते हैं, सब्जी विक्रेताओं से बातचीत करते हैं, भारत के बारे में पूछते हैं। बहुत दिलचस्प है इसको देखना। उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराओं और राजनीतिक चेतना देख सुनकर हमें बहुत सुख मिलता है।

अनेक व्लागर्स के हमने बाजार भ्रमण के कई विडियोज देखें हैं, यूरोप, अरब देशों, अफगानिस्तान आदि के पारंपरिक बाजारों को देखना अद्भुत होता है। पूर्व सोवियत देशों और पश्चिम देशों के शीतकालीन बाजारों की विशिष्ठता भी बहुत अलग तरह से मुग्ध करती है। लेकिन हम यहां उन हाट बाजारों पर अपनी बात केंद्रित रखना चाहते हैं जिनकी दक्षिण एशियाई देशों में खास पहचान और महत्व होता है। कुछ इसी तरह के हाट बाजार हमने अफ्रीका के कुछ देशों में भी कुछ व्लागर्स के माध्यम से देखे हैं जो आदिवासी इलाकों के गांवों और कस्बों में लगते हैं। उनके दृश्य देखकर हमें अपने 50 साल पुराने भारत के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की याद आ जाती है। तंजानिया, युगांडा,केन्या,नाइजीरिया आदि जैसे अनेक देशों के ग्रामीण और परंपरागत बाजारों के नजारे ठीक हाट बाजारों की तरह ही होते हैं। इसी तरह हमने ताइवान के कुछ वीडियो भी देखे हैं। वहां के लोकल किस तरह से सब्जी उगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ग्राहकों को विक्रय हेतु तैयार करते हैं, बाजार ले जाते हैं, ज्यादातर देशों में हम इन बाजारों पर महिलाओं का आधिपत्य देखते हैं। हाट बाजारों का अधिकतम कामकाज महिलाएं संभालती हैं। हमारे देश के उत्तर पूर्वी याने सेवन सिस्टर राज्यों में यह सहजता से देखा जा सकता है। नोमेडिक इंडियन के दीपांशु सांगवान के विडियोज के साथ हमने इन क्षेत्रों का खूब आनंद लिया है।

जो हम बचपन से देखते आए उससे कहा जा सकता है कि गांवों और कस्बों में लगने वाले स्थानीय बाज़ार को हाट बाज़ार कहते हैं। यहां सब्ज़ी, फल, खाद्यान्न, और परचून सामग्री मिलती है। गाँव के लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने में हाट बाज़ार की अहम भूमिका होती है। कुछ दैनिक तो कुछ बाजार साप्ताहिक रूप से भरते हैं, अब हम हमारे शहर की बात करें तो हमारे यहां एक सोमवारिया हाट लगता था, इसी तरह शुक्रवार के दिन किसी और जगह पर हाट भरता था, दिन के आधार पर ही इन हाटों का नाम ख्यात हो जाता है। दिल्ली जैसे महानगर में जनकपुरी की सड़कों पर हमने इसी तरह का शनिवारी बाजार लगते देखा है। उस दिन वहां जाम जैसा लग जाता है, लेकिन उसका भी अपना आनंद है।

बहुत से बाजारों में सेकंड हैंड सामान की दुकानें लगती हैं, इन बाजारों को दक्षिण एशिया में, टर्मिनल बाज़ार या सेकेंड हैंड सामान का बाज़ार, लांडा बाज़ार भी कहते हैं। गैर लाभकारी संस्थानों के उत्पादों या सेवा कार्यों को रेखांकित करने के लिए जो प्रदर्शनी लगती है उसे मीना बाज़ार कहा जाता है लेकिन हाट बाजार की झलक भी इन मीनाबाजारों में मिल जाती है। मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे कुछ देशों में शाम को खुलने वाले रात्रि कालीन बाज़ार को पासार मालम कहते हैं। सुबह के बाजारों को पासार पागी कहते हैं। ये आमतौर पर आवासीय इलाकों की सड़कों पर लगते हैं, खाने पीने के भी स्टाल लगते हैं। सुबह से दोपहर तक इनमें खरीदारी की जा सकती है। कई बार बाजारों की सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए बंद रहती हैं।

कुछ हाटबाजार विशेष अवसरों और पर्वों पर भी लगते हैं। कुछ हाट गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में भी होते हैं जिनका काफी सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व होता है, ये कई पुरानी परंपराओं और रीति रिवाज का हिस्सा बन चुके होते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में होली के अवसर पर लगने वाले हर्षोल्लास से परिपूर्ण भगोरिया हाट। इन हाटों मेलों में आदिवासियों के रिश्ते बनते हैं। ऐसे ही पर्वों पर लगने वाले हाट बाजार और मेले जिन्हे जतरा भी बोला जाता है पर्यटकों की खास रुचि का हिस्सा बन जाते हैं। मध्य प्रदेश के देवास शहर में आषाढ़ी पूर्णिमा पर तीन दिवसीय मेला या जतरा लगती है जिसमे आसपास के ग्रामीण स्त्री पुरुष, बच्चे बड़े उत्साह से शामिल होकर आनंद उठाते हैं। मेले की यह सतरंगी छटा और गहमा गहमी देखते ही बनती है। कहीं शिवरात्रि पर लगता है तो कहीं दशहरे पर। ये मेले भी कहीं न कहीं ग्रामीण हाट का ही विस्तृत रूप होते हैं।

अब इन बाजारों का महत्व सरकारों द्वारा भी समझ लिया गया है और इनका उपयोग क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए भी होने लगा है। हाट बाजारों का अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक महत्व है। सरकारों ने अपनी गतिविधियों को भी जोड़ दिया है। मेलों में आसपास के ग्रामीण लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, अपने परंपरागत परिधानों में आते हैं, वहां लोक कलाएं, लोकगीत के आयोजन होते हैं। हाट बाजारों में हर समाज के हर क्षेत्र के हर वर्ग के ग्रामीण लोग, स्थानीय लोग, आसपास के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। व्यापारी किसान से मिल रहा है, किसान दिहाड़ी मजदूर से। शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक, पुजारी, शिक्षक, सरकारी आदमी, पटवारी सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। पशुपालक है यहां तो पशु चिकित्सक भी मिल जाता है। सामाजिक समरसता और एकजुटता की राह इधर से बनने की गुजाईश निर्मित होती है।

स्थानीय व्यापारियों, छोटे दुकानदारों, किसानों के बीच खरीद बेच से स्थानीय स्तर पर पूंजी का प्रवाह स्थानीय समाज में ही होता है। यहीं की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ होने में आसानी होने लगती है। स्थानीय हुनरमंद कलाकारों, उद्यमियों, बुनकरों, शिल्पकारों कारीगरों को स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध हो पाता है। इस तर्ज पर अब शिल्पग्राम, क्राफ्ट बाजार, हाथ कराघा बाजार, बांस की टोकरियों बनाने वाले लोगों के उत्पादों, लोहे के शिल्प और औजार बनाने वालों के उद्योगों को भी इन हाट बाजार के जरिए महत्व दिया जा रहा है।

हमारे देश में स्वयं सहायता समूह अवधारणा का जो व्यापक माध्यम आया है, जिसमें समूह बनाकर ग्रामीण महिलाएं अपनी उत्पाद गतिविधियों में जुटी हैं, विशेष कर ग्रामीण महिलाओं के समूह है जो गृह उद्योगों में आगे बढ़ी हैं, मसलन मसाला उद्योग, लघु उद्योग में प्रोडक्ट बनाती हैं, साबुन, अगरबत्ती या अन्य जीवनोपयोगी वस्तुएं, इन सब चीजो के विक्रय के लिए इन बाजारों का भी उपयोग होने लगा है। कहीं कहीं इनके लिए अलग से हाट बाजार बनाए गए हैं, सुविधाएं दी गई हैं। हाट बाजार का एक अपना अलग महत्व होता है और एक तरह से देखा जाए तो सारे ही बाजार एक दूसरे पर अब निर्भर करते हैं।

दुनिया के विभिन्न बाजारों को घुमंतुओं के यूट्यूब वीडियो में देखने पर एक अलग ही आनंद आता है। हमे लगता है दुनिया को घर बैठे देखने का यह भी एक अच्छा तरीका हो सकता है।

श्री राम नाट्य समिति ने इस साल पुनः रामलीला का मंचन किया, क्षीरसागर पहुंचे देवतागण, की याचना

सुबह सवेरे सोहागपुर। नगर में विख्यात रामलीला श्री राम नाट्य समिति ने पुनः इस साल रामलीला का मंचन विख्यात गांधी चौक में प्रारंभ कर दिया है। विगत रात्रि में रामलीला मंचन में रावण जन्म, रावण द्वारा तपस्या करके वरदान प्राप्त कर किया । वरदान प्राप्त करके रावण ने देवताओं और साधुओं पर अत्याचार करने का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अत्याचार से क्षुब्ध होकर ब्रह्माजी शंकर जी इन्द्र आदि देवता क्षीरसागर में लक्ष्मीनारायण भगवान के पास जाकर अपनी व्यथा बताई। देवताओं ने भगवान् लक्ष्मी नारायण से पृथ्वी पर शीघ्र नर स्वरूप में अवतार लेने की याचना करते हैं। भगवान् श्री लक्ष्मी नारायण ने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान अयोध्यापुरी में मानव रूप में अवतार लेने का वचन देते हैं ।कि मैं अयोध्या में नरेश राजा दशरथ के यहां नर रूप में अवतार लेकर आऊंगा। अब आप निश्चिंत रहे इस धरा से असुरों का सर्वनाश करूंगा। श्री राम नाट्य समिति के वकील अखिलेश मालवीय ने बताया कि 6 अक्टूबर को मुनि आगमन ,सुबाहू ,ताड़का वध तथा मारीच को बांण प्रहार से सौ योजन पर पहुंचाने की लीला संम्पन्न होगी । 7 अक्टूबर को पुष्प वाटिका, जनक बाजार, धनुष यज्ञ, लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला स्थानीय कलाकारों द्वारा श्री श्री अनिल कुमार जैन की अध्यक्षता में दर्शाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि श्री राम नाट्य समिति इस साल पुरानी परंपरा को बरकरार रखने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में कलाकारों की कमी है ।फिर भी नन्हे बाल कलाकारों के सहयोग से लीला का मंचन किया जा रहा है। आपने आगे बताया कि गांधी मंच पर रामलीला का मंचन वर्षों से किया जा रहा है। उसे नगर के प्रतिष्ठित स्वगीर्य सेठ गेंदालाल जी जैन ने वर्ष 1985 में रामलीला मंचन हेतु बनवाया था । मंच क्षतिग्रस्त है। इसके पुनर्निर्माण व साथ में एक श्रृंगार रूम निर्माण हेतु समिति द्वारा नगर परिषद सोहागपुर व जनप्रतिनिधियों से आवेदन देकर निवेदन किया गया था समिति इस वर्ष पुनः आवेदन प्रशासन को देकर मंच नव निर्माण की मांग करेगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नगर आगमन वर्ष 1932 में हुआ था। इसी स्थल पर महात्मा गांधी ने सभा को संबोधित किया था। इसी कारण यह स्थल गांधी चौक के नाम से विख्यात है। आपने समाजसेवियों एवं प्रशासन से मंच के पुनर्निर्माण की मांग की है।

शनि, रवि लाखों भक्त पहुँचे माता रानी के दर्शनों के लिये, रातभर जागता रहा देवास

देवास/मोहन वर्मा। नवरात्रि के तीसरे और चौथे दिन सप्ताह अंत होने से माता रानी के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में भक्त अपनी अपनी मुरादें लेकर मुरादें पूरी करने वाली मां के दरबार में माता टेकरी पहुँचे । शहर पूरी रात बाहर से आने वाले भक्तों की अगवानी करता रहा और जगह जगह लगे भंडारे भक्तों का स्वागत खिचड़ी,आलू बड़े, केसरिया दुध से करते रहे। प्रशासन के लिए नवरात्रि पर्व पर सबसे बड़ी चुनौती सप्ताह अन्त के दिनों में भीड़ नियन्त्रण होती है और इन दिनों के लिए खास प्लान तय किए जाते है जिससे अतिरिक्त भीड़ की स्थिति में भी भक्तों को परेशानी न हो और सुगमता से दर्शन हो सके। इस बार भी शनिवार की पूरी रात भक्तों की भीड़ उमड़ती रही और रविवार भी हर कोई मां के दरबार में खिंचा चला आ रहा था। मौटे तौर पर शनि रवि को चार लाख से अधिक भक्तों ने माता रानी के दर्शनों का लाभ लिया।

उल्लेखनीय है कि नवरात्रि में देवास के अलावा यों तो जगह जगह से भक्त देवास पहुँचते है मगर इंदौर उज्जैन से पैदल चल कर हजारों लोग देवास आते है और ये सिलसिला रातभर चलता है। प्रशासन और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के स्वैच्छिक योगदान से भक्त भीड़ होने के बावजूद अच्छे से और सुगमता से दर्शन कर पाते रहे है। जिलाधीश ऋषव गुप्ता के दिशानिर्देशों में प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से आपसी समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और हर तरफ माता रानी के जयकारों के साथ भक्त मां के दर्शन कर निहाल हो रहे है ।

कार्य सर्वोच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण किये जायें: पावर ट्रांसमिशन एमडी सुनील तिवारी

इंदौर देवास। एम.पी ट्रांसको के प्रबंध संचालक इंजी. सुनील तिवारी ने इंदौर में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी पश्चिम क्षेत्र की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रबंध संचालक इंजी. सुनील तिवारी ने इंदौर क्षेत्र में चल रहे पारेषण अधोसंरचना विस्तारीकरण के वर्तमान कार्यो, ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों के मेंनेटेनेंस कार्यो की प्रगति की समीक्षा की तथा नवम्बर, दिसम्बर माह में सिंचाई के दौरान इंदौर क्षेत्र में विद्युत की बढ़ने वाली संभावित मांग की चुनौतियों और उससे निपटने के उपायों पर गंभीर विचार विमर्श किया। इस समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि एम.पी. ट्रांसको इंदौर के अधिकारी आगामी रबी सीजन में इंदौर क्षेत्र की संभावित अधिकतम विद्युत मांग को हेंडल करने के लिये तैयार रहें एवं किये जा रहे कार्य सर्वोच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण किये जाये। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में डिस्काम के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार लोड ट्रांसफर करके विद्युत सप्लाई की जानी अपेक्षित है उन्हें प्राथमिकता पर यह सूचना प्रदान कर दी जावे । इस हेतु उन्होंने जबलपुर हेडक्वार्टर से आए हुए अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए।

श्री तिवारी ने कहा कि कंपनी ने सबस्टेशनों के रिमोट ऑपरेशन, ड्रोन पेट्रोलिंग जैसी नई तकनीकों का उपयोग करके तेजी से घट रहे मैनपॉवर जैसी आपदा को अवसर में बदला । उन्होने सभी अभियंताओं का आव्हान किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीक के उपयोग से न सिर्फ अपने कार्य की क्षमता में वृद्धि करें बल्कि अपने कार्यो को अधिक सुगम बनाने हेतु प्रयास करें।। श्री तिवारी ने सभी अभियंताओं से कहा कि यदि वह समझते हैं कि उन्हें किसी विशेष क्षेत्र में ट्रेनिंग की आवश्यकता है जिससे कंपनी के कार्यों में मदद मिलेगी तो वह सीधे उनसे इस हेतु संपर्क कर सकते हैं कंपनी आवश्यकतानुसार ट्रेनिंग की व्यवस्था करेगी।

श्री तिवारी ने कंपनी में लगातार घट रहे मैनपॉवर से बाहर आने हेतु सुझाव दिया कि उच्चाधिकारी जब भी सबस्टेशन या लाइनों की विजिट करें वहां उपस्थित स्टाफ को प्रत्येक प्रकार की संभव ट्रेनिंग प्रदान करें तथा नई तकनीक के बेहतर उपयोग की संभावना तलाशते हुए समीक्षा करें । श्री तिवारी ने कर्मचारी कार्मिकों के आवासीय परिस्थितियों की भी समीक्षा की और कहा कि हमारे कार्मिकों के परिवारों की आवासीय सुविधा में जो भी कमियां हैं उन्हें शीघ्र हल निकालकर दूर किया जावे।

इसके अलावा प्रबंध संचालक इंजी. सुनील तिवारी ने निर्देश दिये कि रबी सीजन के पूर्व सभी आवश्यक मेंटेनेंस एक्टिविटी पूर्ण कर ली जावे तथा आपात कालीन परिस्थितियों में उपयोग आने वाली सभी सामग्रियों और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायें।

सामयिक

डॉ. सुधीर सक्सेना

ईशा फाउंडेशन, वाद और सीजेआई

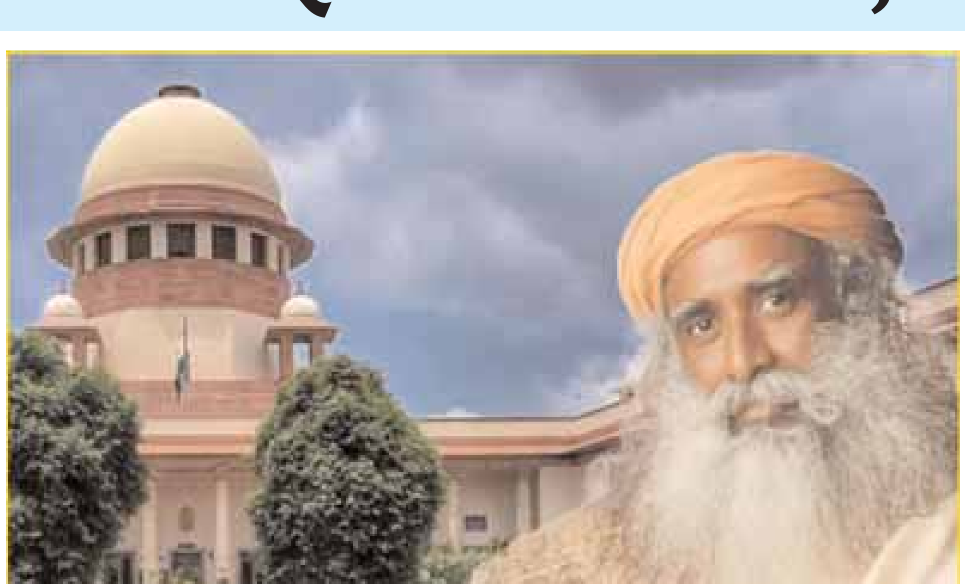

सद्गुरू जग्गी वासुदेव वैश्विक शख्सियत हैं और उनके द्वारा स्थापित ईशा फाउंडेशन को लब्ध प्रतिष्ठित और पंचसितारा न्यास की संज्ञा दी जा सकती है। फाउंडेशन के कोयंबटूर में स्थित परिसर का वैभव देखते ही बनता है। विश्व के नामचीन और गणमान्य जन आध्यात्मिक शांति और आंतरिक रूपांतरण के लिये वहां आते रहते है। सद्गुरु क्रिया (ऊर्जा), ज्ञान, कर्म और भक्ति में जरिये आंतरिक रूपांतरण की पद्धति के प्रणेता हैं और पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता के लिये जाने जाते हैं। संप्रति, सद्गुरु का फाउंडेशन सुर्खियों में है और ये सुर्खियां उपजी है पहले मद्रास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फलस्वरूप। मंगलवार एक अक्टूबर को तब सनसनी फैल गयी, जब करीब डेढ़ सौ पुलिसकर्मियों का दस्ता फाउंडेशन के आश्रम में आ धमका। हुआ यह था कि मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को अपने फैसले में कहा था कि पुलिस फाउंडेशन से जुड़े सभी फौजदारी मामलों का ब्यौरा पेश करें। इस आदेश के पालन में तमिलनाडु पुलिस ने तत्परता बरती और आश्रम पर धावा बोल दिया। अदालती फैसले की पूर्वपीठिका यह है कि सेवानिवृत्त प्रोफेसर एस. कामराज ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि आश्रम में उनकी दो बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है। आरोप संगीन था। हाईकोर्ट ने फैसला दिया और सद्गुरु ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

3 अक्टूबर, गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई की और कहा कि पुलिस फाउंडेशन के खिलाफ कोई जांच नहीं करे। उन्होंने यह भी कहा कि आप पुलिस या सेना को ऐसी जगहों पर दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते। फैसले से पेश्तर उन्होंने दोनों लड़कियों- लता और गीता से अपने चैम्बर में बातचीत की। तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी से रिटायर हुए प्रो. कामराज ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटियों को बंधक बनाकर उनका ब्रेनवाश किया गया है, जिससे वे संन्यासिन बन गयी है। कामराज का कहना था कि उन्हें कुछ ऐसा आहार व औषधियां दी जा रही हैं, जिससे उनकी सोचने-समझने की शक्ति चुक गयी है। कालराज का कहना था कि जबसे बेटियों ने उन्हें छोड़ा है, उनका जीवन नर्क हो गया है।

गीता और लता की बात करें तो बड़ी बहन गीता ने इंग्लैंड के संस्थान से एमटेक किया है। उसे सन् 2004 में उसी संस्थान में रुपये एक लाख की तनख्वाह पर नौकरी मिली थी। सन 2008 में तलाक के उपरांत उसने फाउंडेशन की योग कक्षाओं में भाग लेना शुरू किया। जल्द ही उसकी सहोदरा छोटी बहन भी वहीं आ गयी। दोनों वहीं रहने लगीं। नाम बदला। पिता ने कोशिश की, किंतु उन्होंने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि पिता उन्हें नाहक परेशान कर रहे हैं।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि दोनों लड़कियां सन 2009 में आश्रम में आई थीं। उस वक्त उनकी उम्र क्रमशः 27 और 24 साल थी। वे अपनी मर्जी से वहाँ रह रही हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पुलिस आगे कोई जांच नहीं करे। इस वाद में अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी।

राइट क्लिक

प्रशांत किशोरः मदिरा से आर्थिक, सामाजिक विकास का सियासी दांव

अजय बोकिल

कभी भाजपा सहित देश की कई प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने सफल चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर (पीके) द्वारा अपनी बहुप्रतीक्षित राजनीतिक पार्टी 'जन सुराज पार्टी' की स्थापना को सियासी हल्को में कौतूहल और प्रश्नवाचक भाव में देखा जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि पीके का यह राजनीतिक पदार्पण कई विरोधाभासों से भरा है। वो बिहार की उस घोर जातिवादी मिट्टी में नई जातीय और सामाजिक गोलबंदी के साथ विकास की फसल लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो जातिवाद में गहरे तक सनी है। पीके ने अपनी नई पार्टी का ऐलान बापू की जयंती 2 अक्टूबर को किया। उन्होंने कहा कि वो सत्ता में आए तो राज्य में आठ साल से जारी शराब बंदी को एक घंटे में खत्म कर देंगे। पीके के मुताबिक शराबबंदी से बिहार को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे हर साल 20 हजार करोड़ के राजस्व हानि की चपत जरूर लगी। उन्होंने कहा कि वे शराब से मिलने वाले टैक्स को बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। पीके ने 'जय जय बिहार' दिया देते हुए बिहार और बिहारियों के सम्मान की रक्षा की भी बात कही। राज्य के किसानों की दुर्दशा का मुद्दा उठाते हुए पीके ने कहा कि जन सुराज की सोच भूमि सुधार की है, सर्वे की नहीं। किसानों के लिए सुधार की योजनाएं पांच सालों के लिए लागू होंगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 100 में से 60 लोगों के पास जमीन नहीं है। हमें केवल खाने के लिए नहीं, बल्कि कमाने वाली खेती करनी होगी। पीके ने पार्टी की आइडियोलॉजी स्पष्ट करते हुए कहा कि जन सुराजियों की विचारधारा मानवता पर आधारित है। हम 'ह्यूमन फर्स्ट' को तवज्जो देते हुए ऐसा बिहार बनाएंगे, जहां पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात से लोग रोजगार मांगने बिहार आएंगे। बिहार में गरीब बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा। पीके ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू राज में राज्य में सड़कों, स्कूलों, बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं हुई थी। आज मोदीजी गुजरात में जो फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जहां बिहारी काम करने जाते हैं। पीके ने यह भी कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जन सुराज पार्टी बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी।

जहां तक प्रशांत किशोर की बात है तो वो बिहार के रोहितास जिले के कोनार गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं। उनका उपनाम पांडे है, लेकिन संभवतः राजनीतिक कारणों से वो सरनेम नहीं लिखते। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के बाद पीके ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आठ साल तक सेवाएं दीं। उसके बाद भारत लौटकर सहभागिता में 'सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस' (सीएजी) नाम की कंपनी बनाई। कुछ समय बाद ही उन्होंने चुनावी रणनीति बनाने वाली नई कंपनी आई-पैक की स्थापना की और पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में रणनीतिक सलाह देकर राज्य में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनवाने में योगदान दिया। इसी आधार पर वो 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के चुनावी रणनीतिकार रहे। इस चुनाव में देश में पहली बार भाजपा केन्द्र में अपने दम पर सत्ता में आई। इसके बाद पीके ने कांग्रेस, जद(यू), वायएसआर कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आप आदि कई पार्टियों के लिए विधानसभा चुनावों में रणनीतिकार की भूमिका निभाई और सम्बंधित दलों को सत्ता दिलाने में मदद की। अब पीके चुनावी रणनीतिकार से खुद राजनेता बनने की भूमिका में हैं। गोया कोई सिनेमेटोग्राफर फिल्म निर्देशक की भूमिका में आ जाए। नए रोल में पीके कितने सफल होंगे, नहीं होंगे, इस बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने यह दांव बिहार की उस जमीन पर खेला है, जो राजनीतिक और जातिगत रूप से बेहद सचेत लेकिन विकासीय चेतना की दृष्टि से बहुत पीछे है। पीके राज्य की इस दोमट मिट्टी में मानवीयता, जातीय समरसता, किसान कल्याण और सामाजिक उत्थान के आग्रह के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना देख रहे हैं। उस बिहार को जो, अभी भी बीमारू राज्य के अभिशाप से उबर नहीं पाया है। जबकि चार दशक पहले इस अभिशप्त श्रेणी में बिहार के साथ शामिल रहे अन्य तीन राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश लगभग सभी क्षेत्रों में बिहार से बहुत आगे निकल गए हैं।

इस मायने में बिहार की परंपरागत राजनीति से कुछ हटकर पीके ने रास्ता चुना है। पहला तो है जातीय समरसता का। पीके स्वयं अगड़ी जाति से हैं, जिनकी संख्या बिहार में करीब 15 फीसदी है। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का अध्यक्ष एक दलित और रिटायर्ड आईएफएस अफसर मनोज भारती को बनाया है। मनोज भारती की राजनीतिक पकड़ कितनी है या होगी, यह तो आगे पता चलेगा। उनके अध्यक्ष रहने से बिहार में कई पार्टियों में बंटा दलित और महादलित वोट जनसुराज के खाते में आएगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

वैसे बिहार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की पीके की सोच कुछ हद तक व्यावहारिक है। राज्य में शराबबंदी को खत्म करना नैतिक रूप से सही न भी हो, लेकिन आर्थिक रूप से एक विकल्प जरूर है, बावजूद इसके कि शराबबंदी के कारण बिहार के कई घरों में सुकून भी आया है। इसका एक कारण तो यह है कि बिहार में शराबबंदी हकीकत में कानून और कागजी स्तर पर ही ज्यादा है। सरकारी शराब बिक्री बंद होने के बाद राज्य में अवैध शराब का धंधा खूब फल फूल रहा है। वर्तमान में सत्ता में भागीदार बीजेपी ही आरोप लगाती रही है कि राज्य में शराब बंदी के चलते अवैध शराब की 25 हजार करोड़ की समांतर अर्थव्यवस्था पनप गई है। दूसरी तरफ अवैध और जहरीली शराब पीने के कारण हर साल मौतें हो रही हैं। राज्य सरकार के आंकड़े हैं कि आठ साल में 266 लोगों ने जहरीली शराब पीकर जानें गंवाई तो अवैध शराब रखने के मामलों में 6 लाख लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं और इनमें से भी करीब सवा लाख लोग जेलों में बंद हैं। ऐसे में पीके का यह तर्क किसी हद तक जायज है कि राज्य सरकार शराब बिक्री से हर साल करीब 20 हजार करोड़ की आय प्राप्त कर उसे शिक्षा व विकास के अन्य कामों में खर्च करे। वैसे भी राजस्व आय कैसे बढ़े यह बिहार की बड़ी समस्या है। क्योंकि राज्य अभी भी कृषि प्रधान ही है। इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि करीब 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार का वार्षिक बजट 2.79 लाख करोड़ रू. का ही है, जबकि 8 करोड़ की जनसंख्या वाले मप्र का वार्षिक बजट 3.65 लाख करोड़ रू. का है। एक और हैरानी की बात यह है कि पीके अपने आदर्शों में उन महात्मा गांधी को अव्वल मानते हैं, जिनके मिशन में नशामुक्ति अहम रही है। दूसरी तरफ वो सामाजिक न्याय के पुरोधा अंबेडकर को भी अपना आदर्श मान रहे हैं। दरअसल हर नई राजनीतिक पार्टी के सामने नैतिक संकट यह है कि वो अपने आदर्श पुरूष कहां से लाए? उदाहरण के लिए 'आप' जिस विचारधारा पर चल रही है, उसमें उसके आदर्श भगतसिंह और अंबेडकर हैं। वहां गांधी का महत्व केवल राजघाट पर फूल चढ़ाने और गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने तक ज्यादा है।

अब सवाल यह है कि पीके की पार्टी बिहार में क्या कमाल करेगी? क्या वो अगले विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका में आ सकने की स्थिति में है? देश में शायद दो ही ऐसी राजनीतिक पार्टियां तेलुगू देशम पार्टी और आम आदमी पार्टी हैं, जो अपनी स्थापना के एक साल के भीतर चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हो गईं। बाकी दूसरी पार्टियों को यह लक्ष्य हासिल करने के लिए बरसों संघर्ष करना पड़ा है। पार्टी गठन के पूर्व पीके ने बिहार में साढ़ 3 हजार किमी की पदयात्रा की। माना जा सकता है कि वो बिहार की तासीर समझते हैं। लेकिन राज्य में अगड़े, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित आदि जातियों के वोटों के पार्टियों में पहले से जारी बंटवारे और लामबंदी के चक्रव्यूह को पीके कैसे भेद पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। खासकर तब कि बिहार में अगड़ी जातियां राजनीतिक दृष्टि से हाशिए पर जा चुकी हैं और पीके खुद ब्राह्मण हैं। पीके अपने भाषणों में यूं तो सभी पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन कई राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि पीके की पार्टी का सॉफ्टर कार्नर भाजपा के प्रति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य जद(यू), लोजपा, हम आदि पार्टियों को कमजोर करने के लिए पीके को उतारा गया है। हालांकि इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। पीके जहां गांधीवाद और अंबेडकरवाद के समन्वय का नया राजनीतिक कार्ड खेल रहे हैं, वहीं मदिरा के भरोसे राज्य के आर्थिक, सामाजिक विकास का सपना भी पाले हुए हैं। राजनीतिक रूप से यह कितना कामयाब होगा, यह देखने की बात है, खासकर उस बिहार में जहां हर जाति से शुरू होकर जाति पर ही खत्म होती है।

लेखक सुबह सवेरे के वरिष्ठ संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

माता शारदा के दरबार में पहुंचे पांच लाख श्रद्धालु

प्रभारी मंत्री और वन राज्य मंत्री ने भी किए देवी शारदा के दर्शन

सतना (नप्र)। त्रिकूट पर्वत पर विराजित माता शारदा के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि के चार दिनों में अब तक लगभग 5 लाख भक्तों ने मैहर पहुंचकर माता शारदा के दरबार मे हाजिरी लगाई है। रविवार को मैहर की प्रभारी मंत्री राधा सिंह और प्रदेश के वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने भी मातारानी के चरणों में मत्था टेका। मैहर की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने रविवार को अपने प्रवास के दौरान माता शारदा के दरबार मे हाजिरी लगाई। उन्होंने माता रानी का दर्शन पूजन कर कृपा प्राप्ति की कामना की। रविवार को ही प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी मैहर पहुंचे और उन्होंने भी माता के दरबार मे उपस्थिति दर्ज कराते हुए मत्था टेका।

चौथे दिन दोपहर तक पहुंचे डेढ़ लाख भक्तः शारदीय नवरात्रि के चार दिनों में अब तक लगभग 5 लाख श्रद्धालु मातारानी के चरणों में अपनी आस्था समर्पित कर चुके हैं। छुट्टी के दिन रविवार को दोपहर तक लगभग डेढ़ लाख भक्तों ने माता शारदा के दर्शन किए। पहले दिन भी लगभग डेढ़ लाख भक्तों ने मंदिर पहुंच कर मत्था टेका था। श्रद्धालु मंदिर तक सीढ़ियों और रोप वे के अलावा मंदिर समिति की तरफ से चलाई जाने वाली वैन के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं। सर्वाधिक भक्त सीढ़ियों के जरिए पर्वत शिखर पर विराजित देवी शारदा के दर्शन करने जा रहे हैं।

मेले और श्रद्धालुओं की सुविधाः सुरक्षा के लिहाज से पुलिसिया और प्रशासनिक तौर पर यहां व्यापक प्रबन्ध किए गए हैं। कलेक्टर, एसपी, एडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीएम और सीएसपी लगातार व्यवस्था का निरीक्षण कर जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिवपुरी दौरा आज

- देश की तीसरी जनमन कॉलोनी का करेंगे उद्घाटन, निवोदा गांव के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे

शिवपुरी (नप्र)। गुना-शिवपुरी से सांसद और केंद्र में संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार (7 अक्टूबर) को शिवपुरी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया शिवपुरी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीय मंत्री सिंधिया 7 अक्टूबर को ग्वालियर से प्रस्थान कर सुबह 11 बजे शिवपुरी पहुंचेगे। यहां वह ग्राम हातोद में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत बनाई गई देश की तीसरी जनमन आवास कालोनी का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त वह अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 12:40 बजे पर कोलारस तहसील के निवोदा गांव पहुंचेंगे। यहां सिंधिया पीड़ित शोकाकुल तीनों परिवारों से मिलेंगे। बता दें कि निवोदा गांव में 28 सितंबर की दोपहर बंजारा बस्ती के तीन बच्चों की मौत हो गई थी।

भोपाल-इंदौर समेत आधे प्रदेश से मानसून विदा

पूर्वी हिस्से से 10 अक्टूबर तक लौटेगा, तब तक बूंदाबांदी वाला मौसम

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के आधे हिस्से यानी भोपाल-इंदौर समेत 28 जिलों से मानसून की विदाई हो गई है। ये सभी जिले पश्चिमी हिस्से के हैं। इससे यहां ठंड की दस्तक देने तक सूरज के तेवर तीखे रहेंगे। वहीं, पूर्वी हिस्से से 10 अक्टूबर तक मानसून लौटेगा। ऐसे में कुछ जिलों में बूंदाबांदी होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 4 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया (निम्न दाब क्षेत्र) सक्रिय हो गया है। वहीं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम भी एक्टिव है। इस वजह से पूर्वी हिस्से में हल्की बौछारें गिर रही हैं। 5-8 अक्टूबर को मंडला समेत अन्य जिलों में बूंदाबांदी हुई थी। दूसरी ओर, पश्चिमी हिस्से में गर्मी है। ऐसा ही मौसम अगले चार से पांच दिन तक और बना रहेगा। लो प्रेशर एरिया सिस्टम के लौटने के बाद पूर्वी हिस्से से भी मानसून विदाई ले लेगा।

इन जिलों में बूंदाबांदी के आसार

पूर्वी हिस्से में सिस्टम की एक्टिविटी होने से अगले तीन-चार दिन तक मंडला, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, डिंडौरी और अनूपपुर समेत अन्य जिलों में बूंदाबांदी और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। रविवार के लिए पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मानसून के लौटने से प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का असर बढ़ा है। शनिवार को छतरपुर जिले के खजुराहो में पारा 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। लगातार तीसरे दिन पारा 36 डिग्री के पार रहा है। इसी तरह गुना में 35.6 डिग्री, दमोह में 35.4 डिग्री रहा। इससे अक्टूबर में मार्च-अप्रैल जैसे मौसम का अहसास हुआ।

नवरात्रि-दशहरे तक ऐसा ही मौसमः पिछले 2 साल से नवरात्रि और दशहरे पर बारिश हो रही है, लेकिन इस बार ऐसा होने का अनुमान नहीं है। 10 अक्टूबर तक ज्यादातर जिलों से मानसून लौट जाएगा। सबसे आखिरी में पूर्वी हिस्से यानी- जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग से मानसून विदा होगा।

20 अक्टूबर से बढ़ेगी ठंडकः मौसम विभाग के अनुसार, 20 अक्टूबर तक प्रदेश में ठंडक बढ़ने का अनुमान है। रात में पारा 20 डिग्री के नीचे पहुंच सकता है। हालांकि, दिन में तापमान 33-34 डिग्री के बीच ही रहेगा। अक्टूबर के आखिरी में दिन के तापमान में भी गिरावट होने लगेगी।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

साय मंत्रिमंडल में फेरबदल की फिर सुगबुगाहट

छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय मंत्रिमडल में फेरबदल की अटकलें एक बार फिर शुरू हो गई है। इस बार रमनसिंह मंत्रिमडल में मंत्री रहे दो विधायकों को कैबिनेट में शामिल करने की जबरदस्त चर्चा है। दोनों रायपुर संभाग के विधायक हैं। साय मंत्रिमडल में अभी दो पद रिक्त हैं। मंत्रिमडल के गठन के वक्त एक मंत्री कम बनाया गया था और एक पद बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के कारण खाली हो गया। बताते हैं पहले नए विधायकों को कैबिनेट में जगह देने की बात चल रही थी, लेकिन पहली बार के विधायकों का मंत्री के रूप में परफॉर्मेंस को लेकर कई शिकायतों के बाद नए-पुराने का फार्मूला अपनाने की रणनीति बनाई गई। बताते हैं पहले संगठन पुराने मंत्रियों को साय कैबिनेट में शामिल करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन सरकार के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो गया। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा, यह अभी तय नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सात अक्टूबर को दिल्ली में रहेंगे, ऐसे में हो सकता है उनकी पार्टी के बड़े नेताओं से चर्चा हो जाय।

सुनील सोनी और अवधेश जैन लगे कैम्पेन में

कहते हैं रायपुर दक्षिण से टिकट के दावेदार पूर्व सांसद सुनील सोनी और भाजपा नेता अवधेश जैन प्रचार के लिए गली-मोहल्लों में घूमने लग गए हैं। रायपुर दक्षिण से भाजपा के 50 से अधिक नेता दावेदार बताए जाते हैं। लोगों का मानना है कि सभी दावेदारों में सुनील सोनी का पलड़ा भारी है। एक तो सुनील सोनी का टिकट काटकर बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। दूसरा सुनील सोनी रायपुर के निर्वाचित महापौर रह चुके हैं। कहते हैं टिकट के एक दावेदार दुर्गा पंडालों को चंदा देकर अपना जनाधार मजबूत करने में लगे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से बृजमोहन अग्रवाल आठ बार विधायक रहे। सांसद चुने जाने के बाद उनके इस्तीफे से यह सीट रिक्त हुई है। कहा जा रहा है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में बृजमोहन अग्रवाल की ही पसंद चलेगी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ रायपुर दक्षिण सीट में भी उपचुनाव हो जाएगा।

क्या छग के अगले सीएस दिल्ली से आएंगे ?

केंद्र सरकार में पदस्थ आईएएस सुधांश पंत को राजस्थान, मनोज आहूजा को ओडिशा और अनुराग जैन को मध्यप्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया, उससे साफ लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी अगले मुख्य सचिव दिल्ली से आएंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अफसरों में 1993 बैच के आईएएस अमित अग्रवाल भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं। चर्चा चलने लगी है कि अमिताभ जैन के बाद अमित अग्रवाल मुख्य सचिव के रूप में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। राजस्थान, ओडिशा और मध्यप्रदेश भाजपा शासित राज्य हैं और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन का कार्यकाल जून 2025 तक है। 1989 बैच के आईएएस अमिताभ जैन के बाद 1991 बैच की आईएएस रेणु पिल्लै और 1992 बैच के आईएएस सुब्रत साहू हैं। रेणु पिल्लै छग माध्यमिक शिक्षा मंडल और व्यावसायिक परीक्षा मंडल की अध्यक्ष हैं। सुब्रत साहू को महानिदेशक प्रशासन अकादमी के साथ धार्मिक-धर्मस्व विभाग का चार्ज दिया गया है।

अशोक जुनेजा के दिल्ली जाने की अटकलें

1992 बैच के आईपीएस पवनदेव के डीजी प्रमोट होने के बाद छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा के दिल्ली जाने की अटकलें शुरू हो गई हैं। 1989 बैच के आईपीएस अशोक जुनेजा को सरकार ने अगस्त में छह महीने की सेवावृद्धि दी है। अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ के पहले डीजीपी हैं,जिन्हें सेवावृद्धि मिली है। माना जा रहा है कि अशोक जुनेजा की केंद्र सरकार में अच्छी पकड़ है और वे दिल्ली के ही रहने वाले हैं। 1992 बैच के आईपीएस अरुणदेव गौतम और 1994 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता के साथ जुलाई में पवनदेव डीजी नहीं बन पाए थे। एक पुराने मामले के कारण पवनदेव की पदोन्नति अटक गई थी। पवनदेव को पिछले हफ्ते ही पिछली तारीख से डीजी बनाया गया। पवनदेव 1992 बैच की वरिष्ठता सूची में अरुणदेव गौतम से ऊपर हैं। वैसे तीनों डीजी अभी पुलिस मुख्यालय से बाहर हैं। अब देखते हैं किसको और कब पुलिस मुख्यालय में एंट्री मिलती है।

सरकार को सीना फुलाने का मौका

कहा जा रहा है कि नक्सल मोर्चे पर सफलता से साय सरकार को सीना चौड़ा करने का मौका मिल गया। शुक्रवार को अबूझमाड़ के जंगलों में जवानों द्वारा कई नक्सलियों को मार गिराना और उनमें से 31 के शवों को अपने कब्जे में लेना बड़ी उपलब्धि है। पिछली सरकारों में नक्सलियों के जवानों पर भारी पड़ने की खबरें ज्यादा आती थी। विष्णुदेव साय के राज में नक्सलियों के हताहत की खबरें ज्यादा आ रहीं हैं। यह राज्य के लिए शुभ संकेत है। छत्तीसगढ़ पर नक्सली हिंसा का बड़ा दाग है। नक्सलियों पर लगातार वार कर सरकार दाग को मिटाने में लग गई है।

पीडब्ल्यूडी में प्रमोशन की रेवड़ी

कहा जा रहा है लोक निर्माण विभाग में इन दिनों प्रमोशन की रेवड़ी बंट रही है। विभाग सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता का दर्जा बढ़ाने में लगा है। जल्दी-जल्दी प्रमोशन देने के फेर में विभाग गलत-सही को नहीं देख रहा है। इसके कारण लोग हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। बताते हैं अगस्त महीने में हुए अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता के प्रमोशन का नतीजा अब तक घोषित नहीं हुआ है। चार साल और पांच साल के सीआर के चक्कर में लोग हाईकोर्ट गए और मामला लटका पड़ा है। पिछले दिनों कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के प्रमोशन में भी सवाल उठने लगे हैं। वित्तीय अनियमितता का निपटारा हुए बिना एक अफसर को अधीक्षण अभियंता बनाए जाने की खबर आ रही है। वहीं सहायक अभियंताओं के प्रमोशन को लेकर विवाद की चर्चा है। कहते हैं आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ सहायक अभियंताओं को दरकिनार कर कनिष्ठों को पदोन्नत कर दिया गया।सहायक अभियंताओं के प्रमोशन का मामला कोर्ट में सुलझे बिना ही डीपीसी कर लिए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं।

सुर्खियों में मंत्री जी के ओएसडी

कहते हैं छत्तीसगढ़ के एक मंत्री जी के ओएसडी इन दिनों बड़े सुर्ख़ियों में हैं। चर्चा है कि ओएसडी साहब पूरा विभाग चला रहे हैं। खबर है कि मंत्री से ज्यादा ओएसडी साहब की चलती है। ओएसडी साहब हैं तो कनिष्ठ अफसर रैंक के, पर विभाग के बड़े -बड़े अफसरों को अपने उंगुलियों से नचाते हैं। मजेदार बात तो यह है कि ओएसडी साहब जिस मूल विभाग से हैं,वे इन दिनों उसी विभाग को चला रहे हैं। ओएसडी साहब मंत्री जी के पुराने दिनों के साथी हैं,इस कारण कोई कुछ कहता नहीं और कड़वा घूंट पीकर ओएसडी के फरमान को सुन लेते हैं। कहा जाता है कि ओएसडी ने विभागाध्यक्ष से बिना पूछे ही एक राजपत्रित अधिकारी को निलंबित करवा दिया। विभागाध्यक्ष सरकार की मेहरबानी पर चल रहे हैं, इस कारण उन्होंने भी चुप्पी साध ली। वैसे भी पिछले दिनों इस विभाग की बड़ी किरकिरी हुई और मुख्यमंत्री जी ने विभाग के मंत्री को कुछ बैठकों से दूर रखना ही भला समझा।

रोहित यादव को ऊर्जा विभाग सौंपने के मायने

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे आईएएस अधिकारी डॉ रोहित यादव को ऊर्जा विभाग का सचिव और विद्युत मंडल का अध्यक्ष बनाए जाने के मायने तलाशे जा रहे हैं। ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। अब तक मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद ऊर्जा सचिव और विद्युत मंडल के अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री रहते डॉ रमनसिंह ने अपने सचिव को ही ऊर्जा सचिव के रूप में रखा था। भूपेश बघेल ने तो ऊर्जा सचिव के साथ विद्युत मंडल का अध्यक्ष भी अपने सचिव को बना दिया। रमनसिंह के कार्यकाल में डॉ रोहित यादव मुख्यमंत्री सचिवालय में कुछ समय के लिए रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ लौटने से पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय में थे। इस कारण चर्चा चल पड़ी है कि डॉ रोहित यादव देर-सबेर मुख्यमंत्री सचिवालय में आ सकते हैं।

कांग्रेस को बैटिंग का मौका

कांग्रेस ने न्याय यात्रा के बहाने पिछले दिनों विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ बैटिंग की। इस बैटिंग का परिणाम नगरीय निकाय चुनावों में पता चलेगा। कहते हैं बलौदाबाजार से लेकर कवर्धा कांड ने कांग्रेस के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर दिया। कहा जा रहा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बुरी तरह मात खाई कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में हुई बड़ी घटनाओं ने जान फूंक दी। चुनावों में पराजित होकर दुबके नेता बाहर आ गए तो बड़े नेता एक मंच पर आकर हुंकार भरने लगे। कांग्रेस के लिए लड़ाई अभी लंबी है, ऐसे में नेताओं में कितने दिनों तक जोश बना रहता है,यह देखने वाली बात होगी।